The House reassembled after lunch at Thrity-Three Minutes past two of the clock,

The Vice-Chairman (Shri V. B. Raju) in the Chair

THE APPROPRIATION (NO. 2) BILL, 1975—contd.

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : उपसभाध्यक्ष जी, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

श्री भूपेश गुप्त (पश्चिम बंगाल) : समर्थन करने के लिए आप बैठा भी तो हुआ था ।

श्री रणबीर सिंह : अभी माननीय भूपेश गुप्त जी ने कहा कि समर्थन बैठे-बैठे भी हो सकता है । बात तो उनकी सही है, लेकिन कभी समर्थन करने के लिए अपनी भावना भी प्रगट करनी पड़ती है ।

मैं वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्री महोदय को मुबारकबाद देता हूं कि महंगाई का भूत जो हमारे व्हाइट-कालर्ड क्लास ने देश पर चढ़ाया था वह कुछ कम हुआ लेकिन कम करने की देश को क्या कीमत अदा करनी पड़ी है यह सोचने की बात है । मैं अपने प्रदेश के बारे में जानता हूं । हमारे प्रदेश के अन्दर, पानीपत के अन्दर बिजली घर बनने जा रहा था । भाप का बिजली घर बनाने के लिए हमारे स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ने पंजाब नेशनल बैंक से कर्जा लेने की बात तय की और पंजाब नेशनल बैंक ने उस को 12 करोड़ रुपया कर्ज देना कबूल किया और उस से हमारे देश प्रदेश में इंडस्ट्री कितनी ज्यादा बढ़ती और वह देश के हित में कितनी थी या उस से महंगाई दूर करने में हम कितनी मदद दे सकते थे इस बात का आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं । हमारे प्रदेश में सब से बड़ा कारखाना साइकिल बनाने का है और उस से बड़ा कारखाना सेनीटरी वेयर्स का है और इसी तरह से मोटरों के टायर और दूसरे टायर बनाने का भी सब से बड़ा कारखाना हरियाणा में है और इसी तरह के और भी कई बड़े और छोटे कारखाने वहां हैं । कारखानों की इस पैदावार को हम कायम नहीं रख सके इसलिये कि बिजली हमारे पास नहीं थी और इस लिये 60 प्रतिशत बिजली उन की काटी गयी और उससे उन की पैदावार घटी । यही नहीं, खेत की पैदावार में भी कमी हुई । लेकिन वह पैसा न दिया जाय यह सलाह रिजर्व बैंक के विशषज्ञों न पंजाब नैशनल बैंक को दी । तो वह सलाह कितनी सही थी यह सोचने वाली बात है । इसी तरह से उपसभापति जी आप जानते हैं और आप को भी तजुर्बा है कि हमारे देश के अंदर जितने इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं वह सारे बोर्डस अपने कर्ज का ब्याज भी अदा नही कर सकते । जितना रुपया उन पर लगा हुआ है उस का वह ब्याज भी अदा नहीं कर सकते हैं मैं मानता हूं कि यह तरीका हिसाब किताब रखने का सही नहीं है । उसके साथ साथ उस का एक और कारण भी है जितनी ज्यादा बिजली बोर्ड खर्च करता है उस की दर उतनी ही कम है । गरीब आदमी बिजली कम खर्च करता है छोटे कारखाने वाले बिजली कम खर्च करते हैं, तो उन की बिजली की दर अधिक है । जो आदमी 15 यूनिट तक बिजली खर्च करता है उसकी दर कहीं 45 और कही 35 नया पैसा है, जो आदमी मकान को ठंडा करता है, पानी को गर्म करता है, बिजली से बर्तन साफ करता है और बिजली से खाना पकाता है उस की दर उस के लिये 8 या 9 पैसा फी यूनिट है और कहा जाता है कि चूंकि बिजली देहातों को भेज दी गयी है इसलिये स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड्स अपना खर्चा पूरा नही कर सकत चूंकि कहने वाले वही लोग हैं जिन के हाथ मे अख्तियार है, उन्हों के हाथ में भाषा है, कायदा भी । इस के अलावा स्टेट इलक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से भी वही लोग बोलते हैं । मुझे याद है पंजाब में जब सिंचाई व बिजली विभाग मेरे पास था तो एक बार प्रश्न उठा और उस वक्त मैंने देखा कि जो भाई 40 यूनिट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करते थे उन को बिजली 6 नया पैसा के हिसाब से दी जाती थी ।

जो 15 यूनिट तक इस्तेमाल करते थे उनके लिए 34 पैसे की दर थी । हमारे प्रदेश के अन्दर यह सवाल पैदा हुआ कि आमदनी बढ़ाई जाए । उस समय के हमारे मुख्य मंत्री सरदार प्रताप सिंह

कैरों थे, मैंने उन से कहा कि यह आसानी से हो सकता है। उस पर जो हम पैसा लगायेंगे या लेंगे उससे न खेती की पैदावार पर असर पड़ेगा, न इंडस्ट्री पर असर पड़ेगा। लेकिन उससे असर होगा जो बड़े बड़े भाई है। इसलिए मैंने सुझाव दिया था कि जो भाई 6 पैसे की दर पर बिजली इस्तेमाल करते है उनकी दर बढ़ाई जाए। उनको छोटे आदमी के बराबर कर दिया जाए चूंकि हम देश के अन्दर समाजवाद लाना चाहते है। समाजवाद तभी आ सकता है यदि हम जो आर्थिक तौर पर कमजोर है और उसकी सहायता करें और जो आर्थिक तौर पर शक्तिशाली है उसको कुछ नीचा करें। तो उस समय हमने एक दर की। आज भी हमको याद है कि हमारे प्रदेश के उस समय के वित्त सचिव कैबिनेट में यह प्रश्न उठाते थे कि इससे मर जायेंगे। मैंने उनसे कहा कि कौन मर जाएगा ? ये जो ज्यादा तनख्वाह लेते हैं उन पर असर पड़ेगा। मैंने देखा कि देहात में लोग 15 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल नही करते है। जो डोमेस्टिक घरेलू इस्तेमाल के लिए बिजली खर्च होती है 15 यूनिट से ज्यादा या 40 यूनिट से ज्यादा वह केवल 6 पैसे की दर देते थे और वह बड़ी बड़ी तनख्वाह वाले थे। वह मंत्रालय के सचिव या कारखानेदार थे जो अपने मकानों को ठंडा या गर्म करते थे। तमाम प्रदेश के अखबारों ने उनके खिलाफ आवाज उठाई। हमें उसमें इतनी कामयाबी मिली कि 6 पैसे की बजाय 12 पैसे तक हम उसकी दर ले गये। तो जो स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड का हम घाटा पूरा करते है उसका एक ही तरीका है कि जो भाई बिजली कम खर्च करते हैं उनकी दर कम हो और जो कूलर चलाते हैं, मकान को ठंडा या गर्म करते है उनके लिये दर ज्यादा हो। उस समय यह कहा जाता था कि ये बिजली खर्च नहीं होगी। जब हमने पंजाब में यह फैसला किया तो हम पर यह इल्जाम लगाया गया कि यह बिजली जो पैदा हो रही है उसकी खपत नहीं हो सकेगी, बिजली बची रहेगी लेकिन आज तो देश के अन्दर हमारे प्रदेश और दूसरे प्रदेशों में डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए जितनी बिजली है उसको जितनी ज्यादा से ज्यादा बचाकर खेती व कारखाने में खपाया जाए वह देश के हित में है। यह हवाइट कालर्ड के हित में नहीं है। क्यों हिसाब किताब इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड का गड़बड़ है। उसका कारण यह है कि सरकार के मुलाजिम स्ट्राइक करते है। उनको मंहगाई भत्ता भी मिलता है। उधर विरोधी दल के भाई जो देहात से आते है या शहर से आते हैं चाहे उनके भाई मुलाजिम है या नहीं है, लेकिन तमाम उनकी बातों की मदद करते है और समर्थन करते हैं। जैसे अभी भूपेश जी ने कहा तनख्वाह के बढ़ाने के लिए समर्थन और गेहूं का भाव घटाने के लिए समर्थन करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो सस्ता अनाज खाना चाहते है, सस्ता आलू खाना चाहते हैं, सस्ती चीजें खाना चाहते है क्या वह इस ढंग से चला सकते हैं और जो पैदा करते हैं उनका खर्चा पूरा न किया जाए तो फिर सस्ता मिल सकेगा ? पिछले साल का हिसाब खाता देखें तो हमारे देश के अन्दर विदेशों से ढाई सौ रुपये क्विंटल के हिसाब से गेहूं बाहर से मंगाया गया और 700 करोड़ रुपये का गेहूं खर्च किया गया। मै मानता हूं कि अनाज की कमी से लोगों को भूखे नहीं मरने दिया जाना चाहिए लेकिन प्रश्न यह है कि आया कि हम इतनी पैदावार बढ़ा सकते थे या नहीं ? मुझे याद है कि अभी कुछ पहले भाषणों में गौरे जी ने एक स्वाल किया था अपने प्रदेश के बारे में कि डेढ़ सौ रुपया खर्च हो गया लेकिन पैदा कुछ नही हुआ। अगर कोई भी हमारे देश के अंदर सैक्टर है जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा फीसदी पैसा ठीक इस्तेमाल होता है तो वह खेती का सैक्टर है। अगर आप माइनर इरीगेशन के सैक्टर को देखे तो इसकी जानकारी श्री टी० एन० सिंह जी ने की थी जब वे एक कमेटी के सदर थे शुरु में। उस वक्त भी देखा गया था कि कुओं के लिए जो पैसा दिया गया है उसका 85–90 फीसदी सही इस्तेमाल हुआ है। उसी तरह से आज भी अगर जानकारी की जाए तो मैं मानता हूं कि छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए जितना पैसा दिया गया है वह सही इस्तेमाल हुआ है। छोटी सिंचाई

योजनाओं की तीन प्रदेशों के अंदर तरक्की हुई और सबसे ज्यादा तमिलनाडु में हुई है। आपके यहां भी कोई दो लाख के करीब पम्पिंग सैट्स लगे है आन्ध्र प्रदेश के अंदर हरियाणा और पंजाब के अंदर। जब तमिलनाडु बना था तो मद्रास प्रदेश बंटा था। आपके प्रदेश आन्ध्र प्रदेश के भाई यह समझा करते थे कि मद्रास भूखा मरेगा, मद्रास आन्ध्र के कदमों में गिरेगा। जो कुछ वहां हुआ वह सब आपने देखा। छोटी सिंचाई योजना की वजह से वे अपने पैरों पर खड़े हो सके हैं। दूसरी तरफ हमारा पंजाब प्रदेश है, हरियाणा है जिसका पानी, जमीन के नीचे बहुत स्थानों पर खारा है। वित्त मंत्री जी जो हैं उनके प्रदेश का पानी, जमीन के नीचे मीठा है इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं। प्रधान मंत्री जी के प्रदेश के अंदर भी जमीन के नीचे पानी मीठा है। अगर 700 करोड़ रुपये के ट्यूब वैल वहां गाड़ देते और छोटी सिंचाई की योजना को बढ़ावा देते तो मैं मानता हूं कि आने वाले समय में कम से कम 2-4 साल के बाद अनाज का कभी घाटा नहीं रहता।

अभी आपने देखा कपास के भाव बाजार के अंदर गिरी। कपास यहां तक गिरी कि कपास के लिए सरकारी जो कौटन कारपोरेशन है उसको कपास खरीदने के लिए 1 हजार करोड़ रुपये चाहिए थे और दिए गए उसको सिर्फ 10 करोड़ रुपये। नतीजा यह हुआ कि जो साहूकार मिडल मैन थे उसने कपास खरीदा। हालांकि 104 सरकारी कारखानें हैं और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज के लिए कपास चाहिए थी वह भी सरकारी इरादा है कि उसको भी सरकार ने, रिजर्व बैंक ने पैसा देना ठीक नही समझा। उन्होंने समझा कि यहां पैसे का प्रसार हो जाएगा। पैसे का प्रसार नहीं हुआ बल्कि साहूकार की जेबों का प्रसार जरूर हो गया। वह भाई जिसने सस्ती कपास खरीदी थी अब मंहगी बेचेंगे और पैसा कमाएंगे। जो हमारे वित्त मंत्रालय के विशेषज्ञ है वे देश को क्या इसी तरह से आगे बढ़ाना चाहते है। अभी हाल की बात है आलू का भाव गिरा 18 रुपये क्विन्टल तक। यह उत्तर प्रदेश के भाव रहे और दूसरी तरफ गुजरात के अंदर लोग भूख से मरते रहे। हमारा जो फूड कारपोरेशन है जिसको इसके लिए 1 हजार करोड़ रुपया दिया गया अगर वह 10 करोड़ रुपये के आलू खरीद कर गुजरात के अंदर भेजता तो गुजरात में भूखे लोग जो हैं उनको राहत मिलती। जो भाई आलू पैदा करते थे उनको भी मदद मिलती। लेकिन वह नहीं किया।

उपसभाध्यक्ष जी, उसी तरह से आप जानते है कि सरसों के भाव गिरे। सरसों के तेल को वनस्पति के कारखाने इस्तेमाल नहीं कर सकते यह कहा गया। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कि सरसों के तेल से जो वनस्पति बनेगा कोई नुकसानदेह होगा बल्कि इसलिए सस्ते भाव पर कुछ भाई तेल खा सकेंगे तो। इस प्रकार से जो भाई सरसों पैदा करते है वे तो भूखों मर जायें, लेकिन दूसरे लोगों को फायदा मिलता रहे, यह ठीक बात नही है। एक तरफ तो सरसों पैदा करने वालों को पूरी कीमत न मिले और वह साढ़े तीन सौ रुपये के भाव गिर कर दो सौ रुपये क्विन्टल तक जाय और दूसरी तरफ लोग वनस्पति घी भी न बना सकें तो यह बात समझ में नहीं आती कि यह किस प्रकार की योजना है, कौन-सा सोच या विचार है। आज हमारे देश के अन्दर इस प्रकार की हालत पैदा हो गई है। आज जो भाई खेतों में काम करतेहै या जो मजदूरी करते हैं उनको राशन की चीनी नहीं मिल सकती है और उनको राशन का सस्ता अनाज नहीं मिलता है। लेकिन हमारे मंत्रालयों के जो सचिव है या जो बहुत बड़ी तनख्वाह लेते हैं उनको राशन पर सस्ती चीनी मिलती है, राशन का सस्ता अनाज मिलता है। यद्यपि हमारे देश को आजाद हुये 27 साल हो गये, लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि कुछ भाइयों को मत देने का अधिकार नहीं है, यद्यपि हमने उन को मत देने का अधिकार विधान में दिया हुआ है। हमने ग्रामीण मजदूर को मत देने का अधिकार दिया है, लेकिन हम उसको सस्ता राशन नहीं देते हैं। एक किसान और मजदूर जो स्वयं खेतों में काम करते है उनको भर पेट भोजन नहीं मिलता।

है। हमारी पंचवर्षीय योजनाएं चल रही हैं, लेकिन उनसे देहात के आम आदमी को फायदा नहीं मिल रहा है। मैं पूछना चाहता हू कि इस प्रकार की नीति कब तक चलेगी ? आज अन्य लोगों की तरफ से तनख्वाह बढ़ाने की मांग की जाती है। बैंकों और एल० आई० सी० के चपरासी को भी छः सौ और सात सौ रुपये तनख्वाह मिलती है। यह ठीक है कि जो लोग सरकार का कामकाज करते है उनको रहन-सहन के लिये तनख्वाह मिलनी चाहिये, लेकिन यह बात भी सही है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलना चाहिये। मै यह साफ कहना चाहता हू कि जिस चीज से हमारी जेबों पर असर पड़ता है उसका हम विरोध करेंगे। मै चाहता हू कि हमारे देश मे जो स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं और उनकी दर हैं उसको बढ़ाया जा सकता है जिससे कि वे सरकार को रुपया दे सकें। जब उन्होंने बिजली की दर को महंगा किया उनके लिये जो थोड़ी बिजली इस्तेमाल करते हैं तो उनको उचित पैसा नहीं मिल सका अधिक बिजली इस्तेमाल करने वाले की दर बढ़ायी नहीं जाती है। मैं चाहता हूं कि इस तरह की जो भेदभाव की नीति है, इसको वित्त मंत्रालय जल्दी समाप्त करे। मै यह भी मानता हूं कि पिछले 27 सालों में बहुत से काम हुए है। देहातों की भी उन्नति हुई है, किसानों की स्थिति भी बदली है और मजदूरों की स्थिति भी बदली है, लेकिन जितनी तेजी से उन्नति होनी चाहिये उतनी नहीं हुई है। यह इसलिये हमारे नीति निर्धारित करने वाले भाई हैं, चाहे इधर के हों या उधर के हों, वे अपने पेट के और जेबों के ही फेर में रहे इसलिये वित्तीय अवस्था नहीं सुधरी है।

श्री टी० एन० सिंह (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, मै आज यह सोच रहा था कि इस बार हिन्दी में ही बोलूं। आज हम इस बिल के द्वारा करीब 22 करोड़ रुपयों के खर्च की स्वीकृति दे रहे है। सन् 1975–76 में विभिन्न भागों पर मिलाकर जो खर्च होगा उसकी स्वीकृति हम दे रहे है। इस अवसर पर यह लाजमी है कि इस वक्त जो हमारे देश की आर्थिक स्थिति है उसकी ओर हमारा ध्यान जाये। मै बहुत दिनों से इस बात पर बहुत चिन्तित हूं कि अगर हमारी यही हालत रही तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति के सुधरने मे बहुत समय लग जायेगा और हमें सोचना पड़ेगा कि इस प्रकार क्या हमारी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है ? आज करीब 6–7 वर्षो से मुद्रा स्फिति का जो क्रम हमारे देश में रहा है उसको देखते हुये हमारे देश में कीमतें बढ़ी है, खर्चा बढ़ा है, स्टेटों में डैफिसिट बजट पेश हुये हैं। उसके बाद नोट छपे है और यह सिलसिला इस प्रकार चला है कि टूटता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आज तक इस संबंध में जितने भी तरीके अपनाये गये वे इनफ्लेशन की शृंखला को तोड़ने मे सफल नहीं हुये। यह कहना कि अमुक वर्ष में, अमुक महीने में पुरानी गति से कीमतें नही बढ़ रही हैं और इस तरह से थोड़ा सा संतोष प्राप्त कर लेना ठीक नही है। कीमतें तो बढ रही हैं और उसकी गति में कमी-बेशी हो गई है, किसी महीने कम होगी और किसी महीने ज्यादा होगी, किसी वर्ष ज्यादा होगी और किसी वर्ष कम होगी, लेकिन बढ़ने की जो गति है, वह जारी है। इस तरह की जो हमारी आर्थिक स्थिति है, वह बहुत खतरनाक हालत है।

मैंने योजना बनाने में बहुत कुछ काम किया है और शासन को चलाने के बारे में भी बहुत काम किया है। आज भी जब मैं पुरानी बातों को सोचता हूं, तो मुझे यह ख्याल आता है कि हमने कई गलतियां की है और उन गलतियों को मान लेने मे हमें कोई भी संकोच होना नहीं चाहिये। गान्धी जी के चरणों के नीचे मुझे काम करने का अवसर मिला है। जब गान्धी जी ने सत्याग्रह के सिलसिले में—गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह के सिलसिले में और बिहार में चोराचोरी के सत्याग्रह के सिलसिले में गलती की थी, तो उस समय उन्होंने कहा था कि मैंने हिमालियन ब्लन्डर किया। हमारे राष्ट्रपिता

जिन्होंने हमें राजनीति का क, ख, सिखलाया उन्होंने हमें गलती मानने का रास्ता दिखलाया है । आज उस अवस्था में, मैं जब पुरानी बातों की याद करता हूं तो मुझे यह आवश्यक मालूम होता है कि यदि हमें देश को सही रास्ते पर चलाना है तो यह जरूर है कि हम गलतियों को समझें कि कहां पर हम से गलती हुई है ?

पहली गलती जो हुई है वह यह हुई है कि हमारे पास जो पूंजी थी, हमारे पास जो कम साधन थे, उनको ऐसे अंगों में लगाया ऐसे आर्थिक स्ट्रक्चरों के अंगों में लगाया व इन्वेस्टमेंट किया, जिनका नतीजा हमें आठ या दस वर्षों के बाद मिलता था । मैं यह बात मानता हूं कि स्टील इंडस्ट्री एक आवश्यक चीज है, लेकिन यदि उसके परिणाम दस वर्ष बाद प्राप्त हों और एक स्टील प्लांट अपनी क्षमता के मुताबिक उत्पादन दे, तो उसमें रुपये का दुरुपयोग हुआ, और इस चीज को हमें मानना पड़ेगा । आज हमारा ख्याल है कि करीब तीन हजार करोड़ रुपया स्टील और एलाइड इंडस्ट्रीज में लगा चुके हैं। अगर आज हम पूरा नतीजा निकालना चाहते हैं, तो कम से कम मेरा ख्याल है कि 80 लाख टन फिनिश्ड स्टील हमारे पास होना चाहिये । लेकिन हालत यह है कि आज हमारे पास 50–52–53 लाख टन से अधिक फिनिश्ड स्टील का उत्पादन नहीं है यानी हम 60 प्रतिशत क्षमता पर चल रहे हैं । क्या हम इतने धनी हैं कि इतना रुपया लगाने के बाद भी उस रुपये का जो नतीजा निकलना चाहिये वह न निकले ।

3 P.M. एक गरीब आदमी जब दो-चार रुपए खर्च करता है तो चाहता हूं कि जो कुछ उससे मिल सकता है वह उसे मिले । हमारा गरीब देश है । हमने पूंजी लगाई तो ऐसा मालूम हुआ कि हम सबसे समृद्धिशाली देश है । पूंजी लगाने का नतीजा 50–60 फीसदी से ज्यादा नहीं मिला, यह बड़े खेद की बात है । यह आज नहीं, पहले से जाहिर हो गया था । मुझको योजना आयोग में काम करने का मौका सन 58 में मिला जब हम लोग तीसरी योजना की रूपरेखा बना रहे थे । उसी वक्त द्वितीय योजना के संचालन में जो कमियां रही थीं उनका एक सिंहावलोकन किया गया, सेकिन्ड प्लान का मिड-टर्म एप्रेजल किया गया । वह पुस्तक के रूप में छपा है । मैंने भी उसे पढ़ा और पढ़ने के बाद मुझे यह अनुभति हुई कि जो कुछ भी रुपया हम लगाते हैं उसके मुकाबले नतीजा नहीं निकलता । तब प्लानिंग कमीशन में मैंने कहा कि यह 'इनपुट-आउटपुट' की थ्योरी–इतना रुपया लगाओ, इतना उत्पादन होगा गलत मालूम होती है अनुभव से, इसलिए योजना बनाने के क्रम को हम बदलें । उस वक्त किसी ने यह बात सुनी नहीं बल्कि हमारे कई मित्रों ने, योजना आयोग के हमारे स्नेही सदस्यों ने कहा कि मालूम होता है कि आप उस सम्प्रदाय के अनुयायी हैं जो मूर्तियों को तोड़ने में विश्वास करता है , जो हमने अपनी परम्पराएं बना रखी हैं उन सबको आप तोड़ना चाहते हैं , यह ठीक नहीं है । अंग्रेजी में एक लफ्ज होता है 'आइनोक्लास्ट जिसका अर्थ होता है वह व्यक्ति जो मूर्तियों को तोड़ना चाहता है । तो मेरी ख्याति आइनोक्लास्ट के रूप में हो गई । आज मैं सोचता हूं तो-यह अनुभव करता हूं कि असल में मुझे और जोर से, और तेजी से, और सरगर्मी के साथ अपने विचारों को रखना चाहिए था, मुझे खाली बहुमत को देखकर रुक नहीं जाना चाहिए था । आज मैं यह मानने को तैयार हूं कि अपने साथियों के बहुमत को देखते हुए मेरी ज्यादा हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं उसका विरोध करूं, यहां तक कि जब तीसरी योजना में 10 मिलियन टन की सीमा रखी जा रही थी कि यह हमारा लक्ष्य होगा इस्पात उत्पादन करने का तो मैंने देखा कि करीब करीब 600 मिलियन, रुपयों की डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी पड़ेगी 600 मिलियन नए नोट छापने पड़ेंगे तो मैंने सोचा कि यह कुछ कम किया जाये । इस वास्ते मैंने सलाह दी कि 10 मिलियन टन की जगह 9 मिलियन टन रखा जाय । जवाहरलाल जी मुझसे बहुत खफा हो गए और उन्होंने कहा 'त्रिभवन, तुम भी ऐसी बातें करते हो' । मुझे उन्होंने इंडस्ट्री का चार्ज दिया था । उन्होंने कहा कि बड़ा आश्चर्य है

कि तुम भी लक्ष्य से नीचे जा रहे हो । तो एक मर्तबा कहने की जुर्रत जरूर मैंने की लेकिन उस से ज्यादा मैं नहीं कह पाया । आज मैं खुले सदन में इस बात को कह रहा हूं ताकि यह रेकार्ड पर चला जाय । मैं आज सोचता हूं कि वह बात जो मैंने कहना शुरू की थी उस को और जोर से आगे कहते रहना चाहिए था। लेकिन पंडित जी हमारे बड़े माननीय नेता थे हमारे बड़े थे उनकी विद्या और बुद्धि में मुझे तो बहुत विश्वास था और साथ ही मैं उन का एक छोटा अनुयायी था और इस वास्ते मैं मानता हूं कि मैंने ज्यादा हिम्मत नहीं की और ज्यादा विरोध नहीं किया । तीसरी योजना बनी, उस के बाद चौथी योजना बनी । उस वक्त श्री अशोक मेहता चौथी योजना के उपाध्यक्ष थे । श्री लाल बहादुर शास्त्री उस समय प्रधान मंत्री थे । मुझ से उन से बात चीत हुई । मैं भी योजना आयोग का सदस्य था और मंत्री भी था । तो मैंने उन से कहा कि यह योजना बहुत ज्यादा एम्बीशस है बहुत महत्वाकांक्षी है । हमारे देश में ऐसे नहीं चल सकता । लाल बहादुर जी ने कहा कि हम तो ऐसे क्षेत्रों में रुपया लगाना चाहते हैं कि जिन में हम को उस का नतीजा जल्द मिले । 8 या 10, वर्ष बाद अगर उस का नतीजा हम को मिलता है तो उस से देश में मुद्रा स्फीति होती है, उस से कीमतें बढ़ती हैं । इस वास्ते उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर पर बड़ा जोर दिया और उस वक्त मेरा ख्याल यह है कि चौथी योजना 23 हजार मिलियन की बन रही थी । उन्होंने कहा कि वह 20 हजार मिलियन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और इस पर हमारे मित्र अशोक मेहता बहुत दुखी हुए । मैं ने लाल बहादुर जी का समर्थन किया था उस समय वह ज्यादा दिन जिन्दा नहीं रहे । बाद में इंदिरा जी प्रधान मंत्री हुईं । मैं ने उस वक्त भी चौथी योजना के बड़े होने का विरोध किया था, लेकिन चौथी योजना बड़ी बनायी गयी और आज पांचवीं योजना नहीं बन पा रही है और उसे बड़ा बनाने का उद्योग हो रहा है । इस वक्त तो हमारे सामने कोई खास योजना नहीं है, लेकिन यह जो एप्रोप्रियेशन है यह इस का द्योतक है, यह बताता है कि हम इस साल प्लान पर क्या खर्च करने वाले हैं और शासन पर क्या खर्च करने वाले हैं । जिस गति से हम खर्च कर रहे हैं आर्थिक ढांचे के अंदर उन हिस्सों में जिनका नतीजा 8 वर्ष या 10 वर्ष बाद मिलता है उस से मुद्रा स्फीति बढ़ने वाली है, घटने वाली नहीं है । उस से कीमतें बढ़ने वाली हैं । इस वक्त जरूरी है कि हम ऐसे काम करें जिन का नतीजा 6 महीने में या एक वर्ष में हम को मिल जाय और यदि कोई ऐसा सेक्टर है जिस में 6 महीने में या एक वर्ष में कोई नतीजा मिल सकता है तो वह एग्रीकल्चर सेक्टर है, वह एग्रीकल्चर हस्बेंडरी है और वह छोटे छोटे उद्योग हैं । और आज जब हम अपनी मुद्रा स्फीति को या कीमतों को देखते हैं और देखते हैं उन तमाम दूसरी समस्याओं को जो हमारे सामने नाच रही हैं तो उन में सब से बड़ी समस्या हमारे सामने बढ़ती हुई बेकारी की है । 1920-21 में जब गांधी जी ने असहयोग आन्दोलन को शुरू किया था तो उन्होंने कहा था कि हमारे यहां बेकारों की संख्या बहुत है और हमारी बेकारी का फायदा उठाते हैं कुछ लोग जो विदेशों से माल मंगा कर हम को कपड़ा पहनाते हैं और खिलाते हैं और उस का नतीजा होता है कि हमारे आदमियों को कोई रोजगार नहीं मिलता । उन्होंने विदेशी अखबारों के कानून का विरोध किया । आज एक बड़े दुख की बात है कि जो लोग अपने को गांधी जी की राजनीतिक परम्परा के अनुयायी समझते हैं वे ही लोग स्वदेशी को भूल से गये । मैं आपसे पूछता हूं कि जहां हमारा देश इतना गरीब है जब कि हमारी प्रति व्यक्ति आमदनी करीब साढ़े तीन सौ रुपये प्रति वर्ष है और करीब 40 फीसदी जनता ऐसी है, 4 डिसायल्स जिसे अंग्रेजी में कहते हैं उनकी आमदनी गरीबी के स्तर से भी नीचे है, पावर्टी लाइन के नीचे है, जहां ऐसी स्थिति हो, मैं अपने मित्रों से पूछना चाहता हूं कि हमें क्या अधिकार है इस दिल्ली के बड़े नगर में रहने का और यहाँ एयर कंडीशंड हाल में बैठकर बोलने का और बात करने का और देश की समस्या हल करने का क्या हक है ?

सन् 1916 में गांधी जी बनारस गये थे जब काशी हिन्दू विश्व विद्यालय की नींव रखी

गई थी। उन्होंने एक व्याख्यान दिया, आज तक मझे वह भूलता नहीं है। मेरी उस समय अवस्था 12-13 वर्ष की रही होगी। उन्होंने कहा राजे महाराजे लोग बैठे थे। उस जमाने में राजे महाराजे लोग जब ऐसे अवसरों पर आते थे जहां बड़े बड़े अंग्रेजी अफसर आये और लार्ड हार्डिंग ने नींव दी थी तो वे राजे महाराजे सोने-चांदी, हीरे जवाहरात पहने हुए थे। काशी नरेश हाल है काशी में। वह नज़ारा मेरे सामने आज भी नाच रहा है और उन्होंने उठकर कहा कि आप राजा लोग ये जो पहने हुए है गहने ये गरीब के खून और पसीने से बने हैं, आपको इनको पहनने का हक नहीं है और उन्होंने अंग्रेजी राज्य के और राजा महाराजाओं के बड़ेबड़े अफसरों की विलासिता की काफी आलोचना की। तो मुझे इतना याद है कि वह हिन्दी में बोल रहे थे और धीरे धीरे एक एक करके उनका भाषण सुनकर राजा जो बैठे थे वे उठ कर चलने लगे और गांधी जी देखते थे कि बड़े बड़े लोग जो आये थे अतिथि वे उठ कर चले जा रहे है। मुझे इतना भी स्मरण है कि हम जितने नवयुवक लड़के थे हम बारबार यही कहते थे कि गो आन गांधी जी, गो आन गांधी जी। आप बोलते रहिये गांधी जी, ये नारे हम लगाते थे। इसके बाद मेरा ख्याल है, अगर स्मृति मुझे धोखा नही देती तो महाराजा जो दरभंगा के थे वह सभापति का आसन ग्रहण किये हुए थे, वे भी उठकर चले गये। जब गांधी जी ने देखा-गांधी जी बड़े अनुशासन वाले आदमी थे, हम लोग कह रहे थे कि आप बोलते जाइये, 'गो आन गांधी जी' गांधी जी ने उठकर कहा कि अब तो चेयर में अध्यक्ष महोदय भी नहीं हैं, मैं अब नहीं बोल सकता। वह नहीं बोले। लेकिन उन्होंने हमको एक सीख दी, सादगी की और यह बताया कि हम गरीब के नजदीक जायें, हम भी एक छोटे मोटे जमींदार परिवार के थे, हमारा और हरिजन भाइयों के जीवन स्तर में बड़ा भारी अन्तर था आज कितना अंतर है उससे कहीं कम था। उस वक्त गांधी जी ने हमको सिखाया कि तुम्हें चाहिए कि गांवों वालों की तरह रहें और वहां भिंडी के मकान मे रहना शुरू करें। उन गरीबों की तरह सूखी रोटी खाना शुरू करें (Time Bell rings) जरा आप मुझे क्षमा करेंगे। मैं पहले ही बहुत कम बोलता हूं। अगर आप थोड़ी कृपा करें तो समय दे दीजिए।

उस वक्त हमने वही सीखा और उससे हमारे और हमारे गरीबों के बीच एक संबंध स्थापित हुआ। हम समझते थे कि हमारा देश उन गरीबों में बसता है शहरों के बड़े बड़े प्रासादों में नहीं बसता। आज खेद है कि स्वराष्ट्र मिलने के बाद हम समझते हैं कि हमारा देश दिल्ली में बसता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आजकल बहुत से उस पार्टी के लोग अपने को कांग्रेसी समझते हैं। आप लोग नये कांग्रेसी हैं और मैं पुराना आदमी हूं। मैं समझता हूं कि हम लोग अपने पथ से विचलित हो गए हैं। जो रास्ता गांधी जी ने दिखाया था, गांधी जी का नाम ले करके, गांधी जी की कसमें खा करके भी हम उस रास्ते से अलग हो गये यह हमारी इस वक्त की स्थिति है।

इस बजट को देख करके मुझे सिर्फ इस बात का डर नहीं है कि मुद्रास्फीति हो जाती है बल्कि इस का डर है कि बजट जो बार बार हर साल आते रहते है उसके बाद ऐसा मालूम पड़ता है कि जो गांधी जी की सीख के कारण हिन्दुस्तान की जो पर्सनेलिटी बनी थी, व्यक्तित्व बना था, एक इंडविजुयलिटी बनी थी वह खत्म हो गई। हमारा उद्देश्य मालूम होता है, ध्येय मालूम होता है कि हम जितना ही नजदीक यूरोपीय देशों के पहुंचे हैं उतनी हमारी अवनति हुई है। यह नहीं होना चाहिए। हम जितना नजदीक उस व्यक्तित्व के पहुंचेंगे जो व्यक्तित्व गांधी जी ने दिया था, हमारे देश को हमारे राष्ट्र को, उस व्यक्तित्व पर हम फिर से अगर पहुंच जाए तो हमारे देश की वास्तविक उन्नति हो सकती है। इस वास्ते हमें एक नये ढंग से सोचने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि यह बजट विचारधारा का द्योतक है यदि का

अमूल परिवर्तन नहीं हुआ तो आपका देश बच नहीं सकता। मैं बड़े दर्द के साथ यह कह रहा हूं। मैं कोई पोलिटिकल बात में नेक करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं कोई राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित हो कर नहीं कह रहा हूं। व्यक्तिगत पार्टी की तरफ से नहीं कह रहा हूं। मैं एक भारतीय के नाते कह रहा हूं। इसमें बदलने की जरूरत है। आज जरूरत है उसी नारे की फिर से लाने के लिए जिसमें गांधी जी ने कहा था कि सबसे भारी चीज यह है कि हमारे देश में करीब 40 फीसदी आदमी, बेरोजगार है, बेकार हैं। गावों में थोड़े से आदमियों का रोजगार चलता था, बाकी बेकार थे। उनको साल भर में 2–3 महीने रोजी मिलती थी हरिजन भाइयों को। और भी बहुत से गरीब भाई थे जिन को साल भर काम नहीं मिलता था। बेकारी को दूर करने के लिए उन्होंने पहल की थी। जब तीसरी योजना बन रही थी तो हमने अनुमान लगाया था.....।

दूसरी योजना के अंत में जो आदमी हमारे बेकार थे, अनइम्प्लाइड थे उनकी संख्या तीसरी योजना के अन्त तक 70 लाख तक बढ़ जाएगी अर्थात् सात मिलियन बढ़ जाएगी। इस प्रकार का हमारा अनुमान था। उस वक्त हमारी करीब 35 करोड़ की आबादी थी। हमारा इस प्रकार का अनुमान था कि हमारे देश में लोगों की एक बहुत बड़ी संख्या है जिनके पास एक रोज के लिए भी काम नहीं है। इस वास्ते जब प्लान बनाया जा रहा था तो उसमें एक नया पैरा जोड़ा गया और यह तय किया गया कि डेढ़ सौ करोड़ रूपये इम्प्लोइमेन्ट इन्टेसिव स्कीम के लिए खर्च किया जाय। पंडित जवाहर लाल नेहरू जी की अनुमति से बाद में यह पैरा जोड़ा गया था। उसके बाद सन् 1970–71 में नई कांग्रेस सत्ता में आई तो उसने एक क्रेश स्कीम फौर रूरल इम्प्लाइमेन्ट चलाई और उसके लिए 50 करोड़ रुपये रखे गये। उप-सभाध्यक्ष महोदय, आप भी पब्लिक एकाउन्टस कमेटी के सदस्य रह चुके हैं। उस स्कीम का जो अनुभव हुआ उससे आप पूरी तरह से परिचित हैं। यह 50 करोड़ रुपया यों ही चला गया और कुछ नहीं हुआ। ऐसी बात क्यों हो जाती है? इसका कारण यह है कि हमारी जो नुक्ते-नज़र है, इन समस्याओं को हल करने का जो हमारा तरीका है, वह गलत है। हम सोचते हैं कि कागजी कार्यवाही करके और अनप्रोडक्टिव वर्क पैदा करके हम इस हमस्या को हल कर लेंगे, लेकिन इस प्रकार से यह समस्या हल होने वाली नहीं है। हमको प्रोडक्टिव वर्क देना होगा। गांधी जी का हमारे जमाने में यह सिद्धांत था कि जो चरखा चलाता है उसको दो तीन आने से ज्यादा नहीं मिलने चाहिये, लेकिन उस वक्त आमदनी 80) रु० या 84)रु० थी। अगर किसी को दो आने रोज भी मिले तो गांधी जी कहा करते थे कि कम से कम 12 महीनों में उसको 30–35 रुपये तो मिल ही जायेंगे। इस प्रकार के नुक्ते-नज़र से वे चलते थे और इस प्रकार से मसलों को हल करना चाहते थे और उसी की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता था। मैं नहीं समझता कि यह बात अब भी चल सकती है। मेरा कहना यह है कि आज आवश्यकता इस बात की है कि इन मामलों को हल करने के लिये नये सिरे से सोचा जाये और इस काम के लिय हमें गांधी जी से प्रेरणा लेनी पड़ेगी। गांधी जी ने 50 साल पहले हमें जो प्रेरणा दी थी उसको आज हम भूल चुके हैं। मैं यह नहीं कहता कि उद्योग-धन्धे न खोले जाये। हमें दोनों चीजों को साथ-साथ लेकर चलना होगा। ये दोनों चीजें साथ-साथ कैसे चले, यह बात हमारे योजना आयोग के वर्तमान सदस्यों की बुद्धि में नहीं आ सकती है। हमारी सरकार के पक्ष के जो अधिकारी और सदस्यगण हैं या जो हमारे मंत्रिमण्डल के सदस्य है, मुझे पूरी तरह से नहीं बदला गया, यदि उसमें

इस बात के लिये क्षमा करें, उनकी बुद्धि से भी यह समस्या हल नहीं हो सकती है. . .

(Interruptions)

मैं इस बात को मानता हू कि हमने भी गलती की। गांधी जी कहा करते थे कि मैंने हिमालयन ब्लन्डर किया। हम भी मानते है कि हमने गलती की। इसमें कोई संकोच नही है और इसके कारण मैं अपनी गलतियो को और दूसरों की गलतियों का समर्थन करने के लिये तैयार नहीं हो सकता हूं। इसलिये मै आप लोगों से विनम्र भाव से कहना चाहता हू कि..

श्री रणबीर सिंह : आप फिर इस बारे में सुझाव दीजिये।

श्री टी० एन० सिंह : मै इस बारे मे सुझाव दे सकता हूं, लेकिन घंटी जो बज चुकी है।

उप-सभाध्यक्ष (श्री वी० बी० राजू) : काफी समय हो गया है।

श्री टी० एन० सिंह : मै अपने सुझाव देने के लिए तैयार हू और जब फाइनेंस बिल आयेगा तो मै अपने सुझाव रखने की कोशिश करूंगा। मै इस चीज से भागता नही हूं। जो बात मै कह सकता हूं, उसको मे कहूगा और मैंने कहीं भी है। चौथी योजना क वक्त, जब श्रीमती गाँधी प्लानिंग कमिशन की चेयरमैन थी, तो मैंने उनके सामने कहा था और श्री लालबहादुर शास्त्री जी ने भी उस समय परिवर्तन की बात सोची थी। हम लोगो ने सुझाव दिया था कि हम यह बात नही मानते है कि ज्यादा रुपया लगाया जाये। यह बात मैंने कही थी और आज भी कहना चाहता हूं। काश श्रीमती गांधी जी इस समय यहां पर होती, लेकिन वे आज नही है और इस बात का मुझे खेद है। मैंने उस वक्त कहा था कि जिस रास्ते पर आप चल रहीं है, जिस तरह से आप खर्च कर रही है, उसके लिए आप बाद में रोयेंगी। उस वक्त मैंने बंगाली मे एक दोहा है, जो मैंने उस समय कहा था। मैंने उस समय इस तरह की वार्निंग दी थी और आज भी वार्निंग देना चाहता हू। मै अब ज्यादा इस बारे मे नही कहना चाहता हू और अपनी बात यहीं पर खत्म करना चाहता हूं। आपने मुझे जो समय दिया है, उसके लिए मै आपको धन्यवाद देना चाहता हू।

श्री कल्प नाथ : (उत्तर प्रदेश) : आदरणीय उप सभाध्यक्ष महोदय मै वित मंत्री द्वारा सदन मे प्रस्तुत फाइनेंस एप्रोप्रिएशन बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हू। आज, इस साल हिन्दुस्तान अन्धकार युग से निकल कर एक प्रकाश युग मे प्रवेश कर रहा है। आप जानते है कि पिछले वर्ष हमारे हिन्दुस्तान में मुद्रा-स्फिति का जमाना था। पिछले वर्ष हमारा इंडस्ट्रियरल प्रोडैक्शन जीरो प्वाइंट पर था और पिछले वर्ष हमारी अग्रीकलचर एकोनौमी शैटर्ड हो चुकी थी।

मै आपको बतलाना चाहता हुं कि पिछले वर्ष जहां हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 0.7 प्रतिशत था, वहां इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 4 प्रतिशत बढ़ा है। जहां पिछले साल खाद्यान्नों का उत्पादन 104 मिलियन टन था, वहां इस साल खाद्यान्नों का उत्पादन 112 मिलियन टन हुआ है। इस तरह से हमारा उत्पादन और क्षेत्रों मे भी बढ़ रहा है। हमारा देश आज एक अन्धकार के युग से प्रकाश के युग में प्रवेश कर चुका है और इस के लिये हमारे देश के प्रधान मंत्री हमारी महान नेता के नेतृत्व ही जिम्मेदार रहा है।

आदरणीय, उप-सभाध्यक्ष महोदय, आज दुनिया में बड़े पैमान पर परिवर्तन हो रहे है और दुनियाँ मे समाजवादी परिवर्तन की हवा चल पड़ी है। आप जानते है कि दुनियाँ की बड़ी-बड़ी शक्तियाँ अमरीकी साम्राज्यवाद, कम्बोडिया, थाइलैंड और वियतनाम की जनता के सामने घटने टेक कर झुक गयी है। आप सब लोग जानते हैं कि वियतनामी जनता की आयरन विल के कारण ही वहां की जनता को आजादी दिलाई और उपनिवेश वाद, साम्राज्यवाद और नये सामन्तवाद से छुटकारा दिलाया है। आज हिन्दुस्तान को

तरक्की करने के लिये वियतनामी जनता जैसा दृढ़ रास्ता अपनाना होगा क्योंकि दुनिया के साम्राज्यवादी और सामन्तवादी, दोनों मिलकर समाजवादी कदमों को आगे बढ़ना देना नहीं चाहते है ।

पिछले वर्ष हमने इस सदन मे संविधान की कसम खाई थी कि हम भारतवर्ष की जनता को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलायेगे । अभी टी० एन० सिह जी बहुत सी बातों के बारे मे कह रहे थे, लेकिन मै यह कहना चाहता हूं कि किसी भी देश को आधुनिक खेती का प्रयोग करने के लिये पहले आपको हैवी इंडस्ट्री को प्रायरिटी देनी होगी । मै पूछना चाहता हू कि हिन्दुस्तान में खेती का उत्पादन किस तरह से बढ़ेगा ? इसके लिये हमें सिंचाई की व्यवस्था करनी पड़ेगी, इसके लिए हमे फर्टिलाइजर की व्यवस्था करनी पड़ेगी और बिजली की व्यवस्था करनी पड़ेगी । बिजली कैसे पैदा होगी ? हमने हैवी इलैक्ट्रिकल के बड़े-बड़े कारखाने कायम किए हैं और उनके माध्यम से हम बिजली पैदा करेगे । बिजली के माध्यम से हम फर्टीलाइजर पैदा करेगे और फर्टीलाइजर के माध्यम से हम खेती का प्रोडेक्शन बढ़ायेगे । बिजली पैदा करने के लिये हमें लोहा चाहिये और इसीलिए हमने रूरकेला और भिलाई के बड़े-बड़े कारखाने लगाये है जहां पर लोहा तैयार होगा ।

इसी लोहे के आधार पर नए-नए बिजलीघरों का निर्माण होगा, नए-नए कारखानों का निर्माण होगा । देश मे खेती को आधुनिक बनाने के लिये हैवी इंडस्ट्री को प्राथमिकता देनी पड़ेगी । जब केशवदेव मालवीय ने आयल पोलिसी को पंडित नेहरू के जमाने मे शुरू किया था तो किस तरह से दुनिया क साम्राज्यवादी मुल्कों ने और हिन्दुस्तान के प्रतिक्रियावादियों ने उस आयल पोलिसी का विरोध किया था । इंडियन आयल को प्राथमिकता देकर मालवीय जी ने शुरूआत की । अगर हिन्दुस्तान ने आयल के अन्दर अपनी बुनियादी नीति को नहीं अपनाया होता तो हिन्दुस्तान की आज क्या दुर्गति होती यह मै माननीय टी० एन० सिह से पूछना चाहता हूं । मै पूछना चाहता हूं कि नई खेती बनेगी कैसे ? मै पूछना चाहता हू कि क्या हिन्दुस्तान की खेती बिना बिजली के होगी, क्या बिना बिजली के लिफ्ट पम्प चलेगे । क्या बिना बिजली के फर्टिलाइजर के कारखाने चलेगे, क्या बिना बिजली के बड़े-बड़े लोहे के कारखाने बन सकते है, क्या बिना तेल के हमारा यातायात चल सकता है ? आधुनिक खेती का निर्माण करने के लिये आधुनिक इंडस्ट्री पर देश की इकोनोमी को बेस करना पड़ेगा । जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था देश के नेता पंडित नेहरू ने देख लिया था कि योरोप के मुल्क क्यों तरक्की कर रहे हैं । आज हिन्दुस्तान गाड़ी के पहियों में लिपटकर चल रहा है जबकि योरोप एटमिक युग में प्रवेश कर गया है । आज अगर हमे हिन्दुस्तान को ताकतवर बनाना है तो हमको दुनिया के मुल्कों के साथ एटमिक ताकत बनना ही पड़ेगा । यही कारण है कि ट्राम्बे में डा० भाभा के नेतृत्व मे एटमिक एनर्जी की रिसर्च की नींव डाली गई थी । चाहे एटमिक पावर के प्रोडैक्शन का सवाल हो चाहे स्टील का सवाल हो, चाहे फर्टिलाइजर का सवाल हो, ये बुनियादी उद्योग हैं और इन्हीं उद्योगों को प्राथमिकता देकर हम अपनी कृषि को आधुनिक बना सकते है । और इसके आधार पर हम नये देश का निर्माण कर सकते हैं । नए देश का निर्माण करने के लिए अनेक चीजों के साथ पोलिटीकल विल की भी आवश्यकता होती है जिसकी हमारे अन्दर कमी है, जितनी तरक्की हमको करनी चाहिये उतनी हमने नहीं की । अगर हमे नए हिन्दुस्तान का निर्माण करना है तो डिफेंस एक्विपमैंट का प्रोडैक्शन देश में करना पड़ेगा । अमरीका हमको हथियार देने के लिये तैयार है, करोड़ों-अरबों रुपया देने को तैयार है, अपने शिप देने को तैयार है, अपने हवाई जहाज देने को तैयार है, अपने हैलीकाप्टर देने को तैयार है,

अपने पैटन टैंक देने को तैयार है, लेकिन अमरीका इस बात को बर्दाश्त करने के लिये तैयार नहीं है कि हिन्दुस्तान के अन्दर हैलीकाप्टर बनें, हिन्दुस्तान के अन्दर एटमिक पावर हो, हिन्दुस्तान के अन्दर मिलिटरी का सामान पैदा हो। हिन्दुस्तान के अन्दर कोई चीज पैदा हो सके इसके लिये अमरीका तैयार नहीं है। इस मामले में रूस ने हमारी मदद की। भिलाई में इस्पात के बुनियादी उद्योग को लगाने में रूस ने मदद की। हिन्दुस्तान अपना लोहा पैदा करे इसलिए उसने रूरकेला आदि लोहे के बड़े बड़े उद्योगों में हमारी मदद की। हैवी इलेक्ट्रीकल्स की बुनियाद डालने में उसने मदद की। अभी बम्बई में जो आफ-शोर तेल की खोज हो रही है उसमें रूस के एक्सपर्ट तेल की खुदाई कर रहे हैं। नए हिन्दुस्तान के निर्माण में आवश्यक बुनियादी उद्योगों को लगाने में रूस ने हमारी मदद की इसलिए हम उसके दोस्त हैं। अमरीका ने धन देना तो पसन्द किया, अरबों-खरबों रुपया दिया लेकिन उसने इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं किया कि हिन्दुस्तान के पास अपना निजी बिजली घर हो, हिन्दुस्तान के पास निजी एटमिक रिसर्च हो, निजी फर्टिलाइजर का कारखाना हो, निजी स्टील का कारखाना हो, निजी कपड़े का कारखाना हो, । यही कारण है कि जब हमें आधुनिक इकोनोमी का निर्माण करना है तो सेल्फ डिफेंस प्रोडक्शन करना पड़ेगा। अगर हमने बुनियादी उद्योगों में तरक्की नहीं की, हमने मिलिटरी को बिल्ड अप नहीं किया, हमने अपने कारखानों में हथियार नहीं बनाए अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिये, अपनी इकोनोमी की रक्षा करने के लिये तो दुनिया के और मुल्क हमें बर्बाद कर देंगे, इसलिये इस नीति का प्रतिपादन पंडित नेहरू ने किया था और डिफेंस प्रोडक्शन की नींव डाली थी। यही कारण है सन् '71 की लड़ाई में अपने मुल्क में बने, अपने कारखानों में बने बमों से, हैलीकाप्टरों से अपने देश के टैंकों से दुश्मन को हमने ऐसी गहरी पराजय दी जिसको कि वह आज तक भूला नहीं है।

पाकिस्तान के पास है क्या ? क्या उसके पास बुनियादी उद्योग है ? क्या उनका प्रोडक्शन है ? क्या उसकी बुनियादी नीति है ? इन सवालों पर हम को विचार करना चाहिए। आज सबसे बड़ा सवाल है कि हम ने दुनिया को एक नयी व्यवस्था दी है। साम्यवाद की गुदगुदी गोदी और पूंजीवाद की गोदी से हटा कर हमने देश को नये सिरे से निर्माण करने का एक संकल्प किया है ? यह डेमोक्रैटिक सोशलिज्म पर आधारित होगा। हमने दुनिया को एक नयी राह दिखाने का वायदा किया है जो राह कम्युनिज्म और पूंजीवाद, दोनों से दूर होगी। जिस में न कोई डर होगा और न बड़ा प्राफिट। इस हमारे डेमोक्रैटिक सोशलिज्म में हमारे मुल्क की जनता का पेट भरेगा और इस में हम अपनी जनता के मन को मजबूत करेंगे। इस के माध्यम से ही हम देश की जनता के मन को मजबूत करेंगे और उन को गद्दी में हिस्सेदारी देंगे। हरिजनों, गिरिजनों, पिछड़े और आदिवासियों को देश की गद्दी में हिस्सेदारी देंगे और देश की जनता को रोटी, कपड़ा और मकान और दवा और शिक्षा देंगे। यह वायदा हमने किया है। कम्युनिज्म कहता है कि हम रोटी तो देंगे लेकिन गद्दी नहीं देंगे। अमरीकन कहते हैं कि हम तुम को सहायता देंगे लेकिन रोटी नहीं देंगे, मगर हिन्दुस्तान का डेमोक्रैटिक सोशलिज्म जो है उस की व्यवस्था कहती है कि हम जनता को रोटी भी देंगे और गद्दी में हिस्सेदारी भी देंगे। तो यह हमारा एक नया रास्ता है सारी दुनिया में और हमारे देश को इस रास्ते पर बढ़ता हुए देख कर दुनिया का कोई राष्ट्र हिन्दुस्तान को शक्तिशाली होते हुए नहीं देखना चाहता। आज साम्यवाद और पूंजीवाद में एक संघर्ष है। अमरीकी साम्राज्यवाद और रूसी साम्यवाद में एक कंपिटीशन है और इस के चलते पूंजीवाद के खिलाफ दुनिया के मुल्क एक हैं और इसी लिये रूस हमारी मदद करता है। लेकिन वह हिन्दुस्तान को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में नहीं देखना चाहता। इस के लिये तो दुनिया का कोई राष्ट्र भी तैयार नहीं है।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मंत्री ने पिछले बजट में कृषि पर जितना पैसा खर्च किया, मैं कहना चाहता हूं कि उसे देखते हुए कहना पड़ता है कि हमारे देश की कृषि को सरकार ने नेग्लेक्ट किया है। हमारे देश में 32 करोड़ एकड़ जमीन है जिस में 8 करोड़ एकड़ पर ही सिंचाई की व्यवस्था है। 24 करोड़ एकड़ जमीन पर सिंचाई की कोई व्यवस्था नही है। जिस मुल्क में 24 करोड़ एकड़ जमीन पर सिंचाई की कोई व्यवस्था न हो तो मैं कहना चाहता हूं कि उस में कृषि को नेग्लेक्ट किया जाता है। जितना पैसा उस के लिये रखा गया है उस से दुगुना पैसा रखा जाना चाहिए। हमारी सरकार ने लड रिफार्म्स को लागू करने की बात की, लेकिन उस को वह एक समग्र एक कार्यक्रम के रूप में लेकर सामने नहीं आयेगी। हमारी सरकार ने सिंचाई की योजनाओं को प्राथमिकता नहीं दी। हमारी सरकार ने किसानों की समस्याओं का ठीक ढंग से अध्ययन नहीं किया और जितना ध्यान कृषि पर देना चाहिए था उतना ध्यान सरकार ने नहीं दिया। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की सरकार को एग्रो मिलिटरी एकोनामी को प्रायरिटी देनी चाहिए। जहां एक तरफ हमारे हाथों में खेतों की पैदावार बढ़ाने के लिये यंत्र हों, पैदावार बढ़ाने के लिये दृढ़ संकल्प हों वहां दूसरी तरफ हमारे मन में सीमाओं की रक्षा करने का संकल्प हो और हमारे हाथ उस के लिए सदा तैयार रहें। जब यह दोनों चीजे साथ साथ चलेंगी तभी हमारे देश की तरक्की हो सकती है। क्या हम भूल गये है। हम ने वायदा किया था कि हम चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करेंगे। आज 18 रुपये मन लकड़ी बिकती है और 8 रुपये मन हमारा गन्ना बिकता है। हमारी सरकार ने बचन दिया था कि वह चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करेंगी। बंबई अधिवेशन में हम ने उस के लिये प्रस्ताव पास किया था, आपने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि हम उन का राष्ट्रीयकरण करेंगे, हम ने जनता की अदालत में हलफ लिया था, शपथ पत्र लिया एफीडेविट लिया कि हम चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करेंगे लेकिन इस सरकार ने अपना वचन भंग किया है। इसने चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया और हमारे देश के किसानों और खेतिहर लोगों से उत्पादित जो चीनी आज विदेशी मुद्रा का सब से बड़ा स्रोत है उसमें हम को आमदनी कम हो रही है। अगर सरकार तय कर लेती कि हम कानोडिया, बिरला आदि पुंजीपतियों के हाथ से चीनी मिलों को ले लेंगे और बिहार और यू० पी० की मिलों का राष्ट्रीयकरण कर देगे तो सरकार कहती कि हम को फारेन एक्सचेंज के लिये दुगुनी चीनी चाहिए तो किसान दुगुना गन्ना पैदा करता और हम 5 लाख की जगह 10, 15 लाख टन चीनी विदेशों को दे सकते थे और कितना ही फारेन एक्सचेंज अर्न कर सकते थे। 13सौ करोड रुपया हम को आज क्रूड आयल पर खर्च करना पड़ रहा है और 15 सौ करोड़ रुपया हमको विदेशों से अनाज मंगाने पर खर्च करना पड़ रहा है।

अब हमको फारेन एक्सचेंज मिला केवल आयरन ओर के रिजर्व्स से। आज चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। हिन्दुस्तान के किसानों की रीढ़ को मजबूत करने के लिए गन्ने का मूल्य कम से कम 20 रुपये क्विंटल निर्धारित होना चाहिए। सरकार को संकल्प करना चाहि कि आने वाले 5 वर्षों के अन्दर हिन्तुस्तान की हर इंच जमीन के लिए सिंचाई की व्यवस्था करेंगे नहीं तो हम इस सरकार से खुद कहेंगे कि वह हट जाये चाहे विरोधी दल हमें हटाये या न हटाय। जब तक कोई सरकार, अपने डिटरमिनेशन से काम नहीं करेगी, उसके पास दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी जब तक किसी सरकार ने अपने चुनाव घोषणापत्रों को पूरा करने की क्षमता नहीं होगी, अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने की हिम्मत नहीं होगी उस सरकार की समाजवादी सरकार कहने का अधिकार नहीं है।

आज रुस को दाद दी जाती है। रुस की नकल करो। रूस की प्रोडक्शन में नकल करो।

Let the Government of India copy Russians in having production-oriented economy. Why are they not copying Russians

in having production-oriented economy of the country?

मैं चाहता हूं कि रूस की नकल हो, लेकिन रुस की खेती जैसे बढ़ी, रुस की पैदावार जैसे बढ़ी, रुस में कपड़ा जैसे बढ़ा, रुस में खाद्यान्न जिस तरह से बढ़ा, रुस की मिलिटरी जैसे बढ़ी, इनके लिए हमारी सरकार को उसकी नकल करनी चाहिए न कि फिजूलखर्ची के लिए । हमारे देश ने जितना ऐक्सपोर्ट किया है और जितना इम्पोर्ट किया है उस में 1 हजार करोड़ रुपये का सोना हिन्दुस्तान की सरकार को विदेशों को देना पड़ेगा । यह मामूली बात नही है । आप विदेशों को रोक नही सकते इस नीति से ।

दूसरी बात हमें आपसे यह कहनी है कि आज जो इकानामी चल रही है देश में इसका मुकाबला करता है । हमें संकल्प लेना होगा कि हिन्दुस्तान में जब तक इस देश की जनता को रोटी भर पेट, मोटा कपड़ा , अनाज, दवादारू और शिक्षा की व्यवस्था नही होगी तब तक हिन्दुस्तान का कोई भी आदमी दो हजार रुपये महीने से ज्यादा अपने खर्च नहीं करेगा । अगर सरकार यह कानून बना दें तो हमारे देश में 1500 करोड़ रूपया बचेगा और 1500 करोड़ रूपया प्रति वर्ष की बचत से 5 वर्ष के अन्दर 24 करोड़ एकड़ जमीन की सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है । लेकिन लम्बें लम्बें प्रस्तावों और समाजवाद के नारों से, मुद्रास्फिति पर बहस से हमारी समस्यायें हल होने वाली नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय, दो तीन बातें हमें और करनी है । हमारे देश में स्टील का प्रोडक्शन होता है लकिन 40 परसेंट इन्सटाल्ड कपेसिटी ही यूटिलाइज होती है और करोड़ों रूपयों का फिनिस्ड स्टील आज भी हिन्दुस्तान की सरकार को विदेशों से मंगाना पढ़ रहा है । इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या बात हो सकती है ।

In Japan 100 per cent installed capacity of the steel industry is being utilised, whereas in India only 40 per cent of the installed capacity in the steel industry is being utilised.

फार्टिलाईजर की कपेसिटी हमारी 23 करोड़ टन की है । लेकिन हम 12 करोड़ टन पैदा कर रहे हैं । हिन्दुस्तान की सरकार को यह प्रण करना होगा कि हम अपनी इंडस्ट्री की इंनस्टालड कैपेसिटी का 90 परसेंट जहां यूटिलाईज नहीं होगा उस विभाग के मंत्री को उस मंत्रालय में नहीं रहने देगें । तब यह देश बनने वाला है ।

अन्त मे मै कहना चाहता हूं कि अगर हिन्दुस्तान ने अपनी इकानामी डाईनमाईज नहीं की, तो हमारा प्रजातंत्र समाप्त हो जाएगा ।

If the Government of India does not dynamise the economy of the country, then the Indian democracy will be dynamited from this country and from the whole of Asia.

आज हमारी लाड़ाई चीन से है । हिमालय के उस पार जो देश है, जो कहता है कि बन्दूक की नली से सत्ता पैदा होती है । उसी हिमालय के इस पार यह देश है जो कहता है ।

The Government by consent, the government by democracy, the government of the people, by the people and for the people.

हिमालय के उस पार जो देश है वह कहता है, कि दुनिया में साम्राज्यवादियों से युद्ध अवश्यम्भावी है ।

The war on capitalism is inevitable.

हमारा देश कहता है दुनिया में जीओ और जीने दो । वाडूल सम्मेलन हुआ । अगर इस नीति को और इसके बड़े बड़े दार्शनिकों पहलूओं को हमें हिन्दुस्तान में कायम रखना है तो हिन्दुस्तान की सरकार को एक दृढ़ प्रतिज्ञा करनी चाहिये मैं कहता हूं कि हिन्दुस्तान की सरकार को एक अपनी पौलिटिकल विल विल्ड अप करनी होगी । समाजवाद को लाने के लिए ।

This Government must have the political will. I say that the Indian Government does not have the political will to implement socialism in the country and establish a classless and casteless society, a strong nation, which can guide Asian and African countries for the betterment of the world peace.

श्री भैरों सिंह शेखावत (मध्य प्रदेश) : सभापति महोदय, विनियोग विधेयक पारित होने के पश्चात् इस सरकार को संचित निधि में से विभिन्न पदों के आधार पर धन प्राप्त करने का अधिकार होगा । यह बात सही है कि सरकार ने पिछले वर्षों में आय के जितने भी साधन हो सकते थे उन आय के सारे साधनों पर अपना अधिकार प्राप्त किया है । इसमें सरकार ने इस बात की भी चिन्ता नहीं की कि इन आय के साधनों में वृद्धि करने के कारण हिन्दुस्तान की गरीब जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा । यह उसी का परिणाम है कि इस समय योजनाएं चल रही हैं । योजनाओं के नाम पर अरबों रुपये व्यय हो रहे हैं । लेकिन इसके साथ ही साथ देश में गरीबी भी बढ़ती जा रही है । देश में बेकारी भी बढ़ती जा रही है । कई महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर पिछले वर्षों की तुलना में हमारे देश धीरे-धीरे पीछे जा रहा है ।

सभापति महोदय, अभी टी० एन० सिंह साहब ने योजना का उल्लेख करते हुए यह बताया था कि नीतियों के संबंध में उनके कुछ प्रश्नों पर मतभेद था । लेकिन मेरी कुछ ऐसी मान्यता है कि योजना के नाम पर जो कुछ भी हमने व्यय किया है उसका यदि सदुपयोग होता उसमें दुरुपयोग की गुंजाइश नहीं रहती तो जो कुछ भी योजना के नाम पर हमने धन व्यय किया है उसका जनता को निश्चित रुप से कोई लाभ अवश्य मिलता ।

सभापति महोदय, पिछले एक वर्ष से मैं इस सदन में देख रहा हूं कि सदन के कई माननीय सदस्यों ने कई माननीय मंत्रियों पर और सरकार के कई विभागों के अधिकारियों पर प्रमाण सहित कई आरोप लगाए । दुर्भाग्य से सरकार इस प्रकार के आरोपों के प्रश्न पर अपनी थोथी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना कर बैठी हुई है और उसका परिणाम धीरे-धीरे सारे प्रशासन पर पड़ता जा रहा है । मेरी यह मान्यता है कि जब तक सरकार धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त से सख्त कोई कार्यवाही नहीं करेगी, उस कार्यवाही में चाहे मंत्री शामिल हों, चाहे वरिष्ठ अधिकारी शामिल हों तब तक चाहे आप कितने ही साधन सामने रखें कितनी ही योजनाएं बनाएं और योजनाओं के नाम पर कितना ही अरबों रुपया व्यय करें जनता को उससे विशेष लाभ मिलने वाला नहीं है ।

सभापति महोदय, आपको याद होगा कि पिछले वर्षों में फर्टीलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध आपके ही राज्य आन्ध्र प्रदेश में फर्टीलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए । इस सदन में इस बात की मांग की गई थी कि इस प्रश्न को सी० बी० आई० के द्वारा जांच कराई जाए । सी० बी० आई० ने जांच कर ली और सी० बी० आई० ने अपनी रिपोर्ट में 13 अफसरों के विरुद्ध प्रोसिक्युशन करने की इजाजत मांगी और साथ ही 20 व्यापारियों के विरुद्ध प्रोसिक्युशन करने की इजाजत चाही । यह जांच होने के बाद प्रश्न कई दिनों से ज्यों का त्यों पड़ा है । सभापति महोदय, बात यह है कि आरोप जो उनके ऊपर सिद्ध हुए हैं वे कोई टैक्नीकल आरोप नहीं हैं । उन पर जो आरोप लगे हैं और साबित किए गए हैं वे ये हैं :

(1) Charging Rs. 4,000 extra illegally on each wagon of fertiliser from dealers in Andhra. (2) Abatment in criminal conspiracy for blackmarketing. (3) Violation of the Essential Commodities Act by illegal supply of fertiliser to Tamil Nadu and Mysore, meant for Andhra. (4) Deliberate violation of the Fertiliser Price Control Order.

इसी तरह से 20 डीलरों पर उन्होंने आरोप लगाया है । इस सदन को सुन कर ताज्जुब होता कि सरकार ने उनके विरुद्ध प्रोसिक्युशन की इजाजत नहीं दी । किसी न किसी प्रकार इस प्रकार से व्यवस्था की जा रही है कि इन अधिकारियों का प्रोसिक्युशन न हो । ब्लैक मार्किट करने वाले इस प्रकार के व्यापारी और अधिकारी जो हैं उनको किसी प्रकार दंड न मिले । मैं इस सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या आप उन अधिकारियों को इस विनियोग विधेयक के पारित हो जाने के

पश्चात् उन्हीं के माध्यम से सख्त सजा देना चाहते है जिससे जनता मे विश्वास पैदा हो सके ।

जो धन सरकार को दिया है उस धन का सदुप्योग होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है । यह तो मैंने वरिष्ठ अधिकारियों का मामला बताया है । इसी प्रकार का एक दूसरा मामला है । आई० टी० डी० सी० के चैयरमैन के खिलाफ सी० बी० आई० ने जांच करके रिपोर्ट सरकार को दी । सरकार ने उस रिपोर्ट को दबा दिया । उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही करने के लिए सरकार तैयार नहीं है । मैंने इस प्रकार से दो केस सरकार के सामने रखे, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई । इस प्रकार के मामलों का प्रभाव बाकि प्रशासन पर भी पड़ता है । बाकी प्रशासन के अधिकारी यह समझकर चलते हैं कि यदि उन्हें किसी प्रकार का संरक्षण सरकार की तरफ से मिलेगा तो उन्हें किसी बात के लिए डरने की आवश्यकता नहीं है । मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार और सरकारी अधिकारियों तथा राजनीतिज्ञों का किसी प्रकार से अगर मेल हो जाता है तो किसी भी देश में भ्रष्टाचार चौगना बढ़ जाता है । आपको याद होगा, इसी सदन में कई बार इस बात पर चर्चा हुई कि सन् 1971 के चुनावों के लिये सत्तारूढ़ दल ने धन इकट्ठा करने की दृष्टि से कितने अनैतिक कार्य किये है । सरकार ने कभी उनका संतोषजनक उत्तर नहीं दिया । एक बात मैं मंत्री महोदय की जानकारी में और रखना चाहता हूं । सन् 1970–71 के पहले जिस प्रकार से कुएं मे जंजाल डालकर बाल्टी से पानी निकालने की कोशिश की जाती है उसी आधार पर कामर्स मिनिस्ट्री ने इस बात का प्रयास किया कि किन किन लोगों को इम्पोर्ट लायसेंस देकर धन इकट्ठा किया जा सकता है और इस प्रकार से जो इम्पोर्ट लायसेंस दिये गये और ब्लैक मार्किटिंग किया गया उससे कांग्रेस पार्टी के लिए धन इकट्ठा किया गया । सारे हिन्दुस्तान में इस प्रकार की तलाशी की गई और एक मामला उनको मिला जिसकी ओरिजनल ऐप्लीकेशन सन् 1965 में दी गई थी । सन् 1965 से लेकर 1971 तक 13 बार इसकी ऐप्लीकेशन रिजेक्ट की गई थी और यह रिजेक्ट करने का सिलसिला सन् 1967 में खत्म हो गया । सन् 1967 से 1971 तक इन्होंने कोई आवेदन-पत्र नहीं दिया और न ही किसी प्रकार की कोई मांग पेश की । सन् 1971 मे उसको अचानक बुलाया गया और सन् 1965 में दी गई ऐप्लीकेशन को मंजूर किया गया । इस एप्लीकेशन में यह दावा किया गया था कि मेरे वर्मा के अन्दर कुछ फण्ड्स ब्लौक हो गये है और उन फण्ड्स के एगेंस्ट में इम्पोर्ट लायसेंस दे दिया जाय । आपको यह सुनकर ताज्जुब होगा कि उसने माल इम्पोर्ट कर लिया और शिपमेन्ट भी हो गया, लेकिन सी० सी० अ ई०ई० नहीं मिला । उसका पोर्ट पर माल था । वह दिल्ली दौड़ा आया और दिल्ली से 13 लाख रुपयों का पोलिस्टर फिलामिन्ट का इम्पोर्ट लायसेंस उसने प्राप्त कर लिया । इस शुभकरण दुर्गाधर ने 13 लाख रुपये का इम्पोर्ट लायसेंस प्राप्त कर लिया और लायसेंस लेने के साथ ही बोर्ड के बाजार के अन्दर तीन सौ गुना अधिक दाम पर उसका ब्लैक मार्किट कर दिया । इस प्रकार से सारी धनराशि कांग्रेस के फण्ड के लिए बांट दी गई । इसलिए मेरा निवेदन यह है कि अगर सरकारी अफसरों और राजनैतिक दलों में भ्रष्टाचार के मामले में कोई सहयोग हो जाता है तो उससे इस देश को परमात्मा ही बचा सकता है । इस प्रकार के मामले एक नहीं, कई है । इस सदन में कई बार चर्चा हुई है और यह बताया गया है कि कौटन कारपोरेशन के पास पैसा नहीं है, जूट कारपोरेशन के पास पैसा नहीं है । यह सरकार आये दिन यहां पर समाजवाद की बात करती है । इस सदन को शायद इस बात की जानकारी होगी कि मोदी एक रबड़ टायर का कारखाना चलाने वाले है और उस पर 23 करोड़ 88 लाख रुपये लगाने वाले हैं । इसके लिए उन्होंने 6 करोड़ रुपये के शेयर बेचे है । इसके अलावा दो करोड़ और आठ करोड़ रुपये के शेयर और प्राप्त किये आपको यह सुनकर ताज्जुब होगा कि 12 करोड़

रुपये फाइनेन्शियल इंस्टिट्यूशन्स से प्राप्त किये गये है और ये अर्ध-सरकार इंस्टिट्यूशन्स हैं। एक करोड़ पांच लाख रुपये बाई वे आफ शेयर कैपिटल से प्राप्त किये गये। एक करोड़ पांच लाख रुपये अन्डरराइटिंग आफ शेयर्स से प्राप्त किये गये। इस प्रकार से 22 करोड़ रुपये अब तक प्राप्त किये जा चुके हैं। उन्होंने एक पैसा भी अपनी जेब से नहीं दिया है। जो पब्लिक मनी है वह सब मोदियों को दे दिया गया है। मोदियों का जो मैनेजमेन्ट है उसने एक पैसा भी अपनी जेब से खर्च नहीं किया है। यहां पर सरकार कई बार समाजवाद की चर्चा करती है और कई बार जोयन्ट सेक्टर की भी बात की जाती है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मोदियों की रबड़ फैक्ट्री के मामले में जोयन्ट सेक्टर की कोई योजना नहीं चलाई जा सकती थी ? आपने 22 करोड़ रुपये सरकारी खजाने से दे दिये। जनता का पैसा उन मोदियों को दे दिया जिनको आपने पद्मश्री की उपाधि दी है और जिनको यहां पर स्मगलिंग के मामलों में गिरफ्तार किया जाता है और जिनको फ्लोर मिल में आटे के मामले में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में गिरफ्तार किया जाता है। इस प्रकार के व्यक्तियों को इस सरकार के द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है। मेरे पास इस बात के प्रमाण है कि चुनावों के दिनों में इनसे कांग्रेस ने धन लिया है। अगर कोई माननीय सदस्य चाहें और इस बात की जांच करना चाहें तो मैं बैंकों के चैक और ड्राफ्ट दिखाने के लिए तैयार हूं। और किस प्रकार से मोदी वालों ने यह सारी कार्यवाही की है और कांग्रेस पार्टी को पैसा दिया, है। इसमें किस प्रकार से ट्रांजैक्शन हुआ है, यह बात सबको मालूम है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के जो तत्व हैं, चाहे वे सरकार में हों, चाहे मंत्रियों में हों, चाहे राजनीतिक दलों में हों, अगर उनका संगठन बन गया, तो फिर इस देश को बचाने वाला कोई नहीं है।

मैं अन्त में यही कहना चाहता हूं कि आप विनियोग विधेयक द्वारा जो धन ले रहे हैं उस धन की सुरक्षा के लिये आपने पहले वादा किया था कि हम लोकपाल बनाने का बिल पास कर देंगे, लेकिन आप अभी तक उस बिल को नहीं लाये हैं जब कि देश में भ्रष्टाचार दिन प्रति दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। देश की जनता का धन सुरक्षित रूप से खर्च हो रहा है, जनता के पैसे का सदुपयोग हो रहा है, इस प्रश्न पर आत्म-विश्वास पैदा करने के लिये आप निश्चित रूप से कोई व्यवस्था करें जिससे हमारे देश में जो भ्रष्टाचारी तत्व है, वे समाप्त हो जायें।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

SHRI DWIJENDRALAL SEN GUPTA (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am sure the Appropriation Bill will be passed and the amount asked for will be allowed to be spent. But certainly for members of the House this is an occasion when we can raise certain questions as to how the money is to be spent, how the money should be spent. That allows me to indicate the functioning of the different Departments of the Government. Now, time is short and within this short time I shall try to indicate some of the points on which the House should be informed and things should be set right.

The first thing of importance to me is the Farakka Barrage. This is the life-line of the economy of West Bengal *vis-a-vis* India. Hundreds of crores of rupees were spent on this, but now what we see is that the purpose is going to be lost because of the demand of Bangladesh. What we see is that Calcutta is getting 11,000 cusecs of water—something like that—whereas requirement of 45,000 cusecs of water was considered necessary. Why so? The reason is not far to see. I have no quarrel with Bangladesh or any part of India. The difficulty is with planning and expenditure. Since the Farakka scheme was passed, at least 21 projects were passed by different authorities, as a result of which water has been drawn from the Upper Ganges in U.P. and Bihar. So there

is shortage of water. The matter requires serious consideration. But for these 21 or 22 plans sanctioned from Upper Ganges, this thing would not have happened. Now hundreds of crores of rupees are going to be totally lost. This is how we are spending public money.

Then, Mr. Vice-Chairman, Sir, on the investment side, banks have been nationalised. But what is the utility and purpose of this nationalisation unless the money reaches the poor men? United Bank of India wanted to give money to the poor agriculturists through one Lok Brati Sangh, which is not a commercial organisation but a social organisation.

4 P. M.

It is a purely social organisation. Now, suddenly, the United Bank of India has stopped financing saying that unless they pay all the money which has been paid to the cultivators, they will not get further money. Now, an amount of Rs. 8 lakhs will be lost unless the United Bank of India continue financing this Lok Brati Sangh to enable it to continue with the scheme. This has been a very bad policy on the part of the United Bank of India to stop financing the Sangh.

As regards Inchek and National Rubber, the two concerns of West Bengal, I have to say that these two concerns have only a fractional percentage of investment. In both the cases, their investment is about 5 to 6 per cent. They are being run completely by Government money. The banks have financed them fully. These companies are guilty of mismanagement, corruption and all that. This is in the audit report of the Company Law Department. But they are again and again paid money. I do not know why and what for and how will the Government realise the money from them. There is one institution, known as IRCI, Industrial Rehabilitation Corporation of India. The purpose of the IRCI is to finance the sick industries. Now many industries have developed a character by which they declare themselves as sick and in the process they take Rs. 10 lakhs or Rs. 20 lakhs crores from the Government through IRCI and thus cheat the Government. Unless there is a complete reorientation in the idea of financing, this money will be a total loss and no sick industry will be able to stand on its legs. Whenever the IRCI people go, finance and take charge of any industry, they only increase their overhead expenditure. I feel their overhead expenses should be reduced, and more honest approach to the matter. This has been their character. The whole thing is now a racket. It is people's money and I think this IRCI is doing more mischief than good. There should be an account of the services rendered by the IRCI so that we know what they have done. So much money is being wasted. Of course, the idea of IRCI is good but its implementation requires a probe.

Now, the Jute Corporation of India was formed to buy jute from the jute growers so that these people do not die, so that their products do not go into the hands of others who usually profit out of it. But what has been the functioning of the Jute Corporation of India? It has not purchased jute and the jute growers have been reduced to a position of complete non entity in the whole process of jute industry as if jute is something for which there was no market. Market is there. This artificial absence of buyer's market was created and that was due to wrong functioning of the Jute Corporation of India.

Mr. Vice-Chairman, Sir, there is the aspect of giving pension to the freedom fighters. We are spending this money without any seriousness of purpose. After 25 years of our independence, we suddenly, thought that the nation has some obligation, some duty to perform for the cause of freedom fighters and a rule was prescribed that those who suffered six months in jail will be eligible for this pension. There are people who spent 20 years of their life in jails and 25 years in jail.

Freedom fighters who have been in jail for six months, five years, ten years and twenty years are all put on the same level and pay Rs. 200 per month as pension. The Government say that if they have any dependents, then we shall consider their case for higher pension but there are people who spent twenty years in jail and had no occasion either to marry or to have

children. So, the question of their dependents as defined by the Government does not arise. If you want to recognise the contribution of freedom fighters, you must make a distinction like this: six months and above up to five years; five years to ten years; ten years and above and do not insist on dependents. Nowadays a sum of Rs. 200 for a veteran revolutionary who is sixty, seventy or seventy-five is nothing. These considerations should be there. The Government should come forward with their scheme in respect of freedom fighters with all sincerity of purpose and in a rational way. Why do you give Rs. 500 to somebody and Rs. 400 to somebody? Is it due to canvassing? That should be obviated. **(Time Bell Rings).**

Similarly, I wish to submit that there are cases of revolutionaries like Harichaitanya De of Kalta bazaar shooting fame. There was a confrontation with the British Government in 1915. The British people were armed. Nalini Bagchi and Tarini Mazumdar were shot dead. Only one man out of the three survived and he was sentenced to 14 years rigorous imprisonment. His son, Bimalendu De, was then only three months old when his father was undergoing imprisonment for fourteen years. His son obviously could not have any education asd did not have any shelter even his relations did not look after him and he had to pass his days in extreme misery as a street boy. He could not thus develop to the extent as anybody else could have. All such sons of freedom fighters are eligible within the scope of the Government's rule for freedom fighters' pension; though ordinarily a son is not eligible. The West Bengal Government has recommended the case to the Central Government for granting him pension. This was about seven or eight months before. The file is being controlled by certain officer here who will not give due weight to that recommendation. He seems to be interested to know the basis of the West Bengal Government's recommendation and he wrote letters to the West Bengal Government. The West Bengal is not replying, I am told. Certainly a son is not ordinarily entitled to the pension, but under special circumstances he is entitled to it. This is also in the rule. It may be reasonably presumed that the West Bengal Government knew this rule and the Advisory Committee, presided over by no less a person than Shri Asok Sen, a retired Judge of the Calcutta High Court, knew how to interpret facts and law relevant to the matter before making his recommendation. If the two Governments themselves thus create a deadlock, should the freedom fighter's son Shri Bimalendu De, suffer and suffer indefinitely? Let the Minister reply.

I have so many cases, but only one more case I would mention. It is the case of Mr. Harishchandra Das Gupta, he is more than 82 years of age. His revolutionary contribution is not in question. He was for many years in jail in the cause of the country's freedom. His case has been recommended by the West Bengal Government more than a year ago. After that recommendation, somebody, I am told, has written a letter to the Government saying that this person's income is more than Rs. 5,000 a year.

It may be an anonymous letter or it may be a signed letter; or it may be a malicious letter or a true letter. But on the basis of that letter, this case has been withheld for more than a year. If tomorrow this man dies and the Government comes up with a report that the letter was a malicious one, what will be our face? What will be the explanation? Why in such cases you do not enquire through your own agencies. I am not pleading for anybody to get them some pension through false or fraudulent means. I want the Government to act promptly. For the last two or three years, all these applications are being held up. This is a recommended case. This man has sworn on affidavit about his income. How can that be **prima facie** disbelieved?

In the sanction orders, there is no limit to the errors—the name is mistaken, the address is mistaken and the amount is miswritten. This is how the Government is treating the freedom fighter as if they are beggars which was never the idea at its inception. Even today these freedom fighters are suffering very much for the delay in sanctioning and callous handling of the whole matter.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): The Minister.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Mr. Vice-Chairman, Sir. . . .

SHRI BHUPESH GUPTA: Have you been weighed against the gold from the Jaipur Palaces to find out which is weightier, you or the gold?

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I am grateful to the hon. Members who have made their observations on the second Appropriation Bill. Though many of them are not present here now, I would like to cover some of the points which they have mentioned.

Sir, Shri T. N. Singh very correctly pointed out that if the present trend in the economic situation continues unabated, the country will definitely be landed in a very difficult situation. At the same time, perhaps in his wisdom, he has overlooked some of the salient features—the serious efforts of the Government to change the track and to bring back the economic forces to normalcy and to do away with the distortions that have taken place. It is no use giving a chronological history of what happened during the days of 1958-59 when he was in charge of the Planning Commission, either as member or as Ministry. What would have been the position of the country if his advice had been heeded? At the same time, certain courses taken by the Government in a very difficult situation like this would indicate that it has been possible to restrain some of the very undesirable forces and to set the economic forces of the country on the right track. While introducing the Bill for consideration, I pointed out—and it has been said on earlier occasions also on the floor of the House—that we had to pass through a very difficult situation in which during the third week of September, 1974 the country reached the record price hike of the order of 330 points or something. There was more money circulation, low productivity, stagnation in industrial growth, retardation in agricultural production. At the same time, the role of black money had a tremendous effect on the economy as such, and distortions took place in various directions.

At the same time, Sir, I hope the hon'ble Member would appreciate the new measures particularly the fiscal measures and monetary controls which were enunciated with the approval of this House and the other House. They have created a sobering influence.

[The Vice-Chairman (Shri Jagdish Prasad Mathur) in the Chair].

As I have already mentioned, perhaps India is one of the few countries where ascendency in the prices has been checked, where prices have been reduced to a considerable extent. At the same time, Sir, I am very much careful when I am making this observation that there is no scope for complacency. At the same time the hon'ble Members would perhaps agree with me that we should not over-simplify the problem merely by saying that seasonal factors contributed to the price decline; perhaps that would not be correct because previously also seasonal factors were there, say, in 1972-73 and 1973-74 but they could not check inflation and rising prices. Therefore, modestly we can claim that the measures taken by the Government had some sobering effect which made it possible not only to arrest the ascendency in prices, not only to stabilise it at certain point but declining trends are clearly visible. At the same time, Sir, perhaps you will agree with me that the factors which are dominating our economy are not limited to geographical boundary of this country. No country today can claim that merely by controlling the domestic fiscal and monetary policies the problem which is basically of an international character can be solved particularly in a developing country like ours when we have to import so many materials for our industrial development or agricultural development. We have to agree that international economic forces have their effect.

Sir, I would not like to justify the causes of inflation by saying that it is part and parcel of the global phenomenon. But as an humble student of economics, Mr. Vice-Chairman, I would like to point out that

if there is a tendency of stock-piling in the international market it would have its effect on Indian economy. If as a result of the uncertainty of dollar there is a tendency of converting the dollar into goods in the international market, perhaps no fiscal policy, accepted and pursued in the domestic field, could avert the difficult to a considerable extent. Same is the case with petroleum and other products. I am just mentioning it to highlight that we had to pass through a difficult situation and the Government tried its best to rise to the occasion and to see in what possible manner they could take care of the problem.

These are the points which have been discussed many a time on the floor of this House. I hope hon'ble Members will get the opportunity again when the Finance Bill will be presented to the House for discussion.

Coming to an important point which many hon'ble Members have mentioned regarding the smuggling activities. The Government is accused of slackening its measures against the smugglers.

I do feel the concern and anxiety of the Members when some of the top smugglers have been set free at the judgment of the High Court and when there are indications in the press—and even in the intelligence report, I have admitted on the floor of this House while replying to a question, there are some visible indications —that smuggled goods are coming into the market. Therefore, I do not blame the hon. Members who have criticised the Government on this account. But at the same time, I would like to place certain facts before the hon. Members and would request them to come to their own conclusion in an objective manner.

Sir, it is known that on the 17th September, 1974, by issuing an Ordinance, the MISA was applied to the smugglers. It was converted into law by this very House under the name of COFE POSAA on the 19th December. The total number of persons put behind the bars was of the order of 500 on the 19th December, 1974. The total number of detention orders would be more. Now, the total number of detention orders issued up to the 26th April, 1975, is 993. The total number of raids that took place between September and December 1973 was 2,200. The total number of raids which took place between September and December, 1974 was of the order of 3,000. The total value of goods seized from September to December 1973 was of the order of Rs. 2.20 crores. Correspondingly the total value of the goods seized from September to December 1974 was of the order of Rs. 1.8 crores. The number of income-tax raids between April and September 1974 was 623. The number of income-tax raids from October 1974 to March 1975 was 1,401. These figures I am quoting only to indicate that the number of raids is increasing both on the income-tax side . . .

DR. K. MATHEW KURIAN: Mr. Pranab Mukherjee, will you give the percentage of the smugglers arrested to the total number of smugglers in the country? According to one estimate, you have arrested only 3 per cent of the smugglers.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I am coming to that point. Please have some patience. I patiently listened to you. My contention is that if more and more people are put behind the bars, if the number of raids is increasing, if searches and seizures go on unabated, then what is the evidence on the basis of which you come to the conclusion that the Government is slackening its activities against the smugglers? What is the conclusive proof for the charge that the Government is not taking effective steps against the smugglers, that there has been a shift in the Government's policy, that the Government has started soft-pedalling against the smugglers? There are no such indications. The figures speak something else. Dr. Mathew Kurian is speaking of percentage.

SHRI BHUPESH GUPTA: How do you say you want to enforce when we know that Mr. Badami, who was in the Inspectorate and was entrusted with the responsibility of conducting the drive, has been suddenly transferred like many other officials, like those of the Central Bank of India and the Bank of Baroda, to which I hope, you will come later?

SHRI PRANAB MUKHERJEE: You have already mentioned that point and I have noted it. I will reply to that question. But what I was saying was, Dr. Kurian mentioned yesterday that only 3 per cent of the smugglers have been arrested and the other 97 per cent are free. I do not know what his source of information is, whether he has collected any statistics about the number of smugglers spread over the country and whether he maintains any census. If he maintains, I would like to have some assistance from him. But my only contention is that when the Bill was passed, the party to which Dr. Mathew Kurian belongs, opposed tooth and nail the passage of that Bill as if we were trying to jeopardise the individual liberties of these persons.

In spite of that . . .

DR. K. MATHEW KURIAN (Kerala): You used MISA to arrest our Party people. The number of our Party people arrested under DIR and MISA is larger than the number of smugglers arrested.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Dr. Kurian is absolutely evading the issue. Does he mean to say that all these 993 people belong to his Party or some of them belong to his Party? If he says that some of them belong to his Party, I am ready to release them.

SHRI SANAT KUMAR RAHA (West Bengal): Why?

DR. K. MATHEW KURIAN: Some time back I produced a photograph in this House of a Minister of the erstwhile V. P. Naik Ministry having spirituous relaxation with one of the biggest smuggler in West Coast, Javeri. Are you prepared to arrest him?

SHRI PRANAB MUKHERJEE. Dr. Kurian may have shown some photograph. Whether he was in spiritual relaxation or spirituous relaxation, I do not know. Photographs are misleading and I hope Dr. Kurian will not be guided by these photographs. Dr. Kurian might himself be photographed with some undesirable people in one of these days when he is in an absent-minded mood. He should be careful about photographs. Photograph is not a conclusive proof or evidence.

DR. K. MATHEW KURIAN: You are talking fiction.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I am talking of facts; not of fiction. My contention is that the number of raids has increased; the number of searches has increased and the number of arrests has increased. Still some people go on saying that Government have slackened their anti-smuggler operations and they are soft-peddling because election is coming.

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत (राजस्थान) : आपने इतने नम्बर बतलाकर यह बतलाने की कोशिश की है कि हमने इतने लोगों को अरेस्ट कर लिया है । लेकिन क्या यह सही नहीं है कि आपने छोटे मोटे लोगों को ही गिरफ्तार किया है और उन्हें गिरफ्तार करके यह नम्बर बतला दिया है । लेकिन इनके पीछे जो कि-परसन्स है, उनको आपने नहीं पकड़ा है और वे अभी तक अपना धन्धा कर रहे हैं ।

SHRI PRANAB MUKHERJEE. This is very much unfair . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI J. P. MATHUR): You take the list from the hon. lady Member.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: If they are not top people, I would request the hon. Members to give me a list of top people. There is no use making a blanket charge. How do they know that these are small people? Haji Mastan is not a small man. If she can give me a list of top people, we shall take action against them. It is no use giving a certificate that all these 993 people against whom detention orders are passed are all small people or some of them are small people. This act is an extraordinary measure. You will recall that when I piloted this Bill on the Floor of the House I said that I wanted to bring a number of big fish within the purview of this Act because direct evidence is not available under Gold Control Act and Customs Act and therefore these people could not be produced before the court. That is why we wanted to have some

extra-ordinary measure to deal with an extra-ordinary situation. However, if still some big fish is out of the net, I would like to have information. It is no use making a blanket charge or allegation in a general way that only small people are caught and big people are outside the net.

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : जिन लोगों के बड़े-बड़े होटलस है, मल्टी स्टोरी बिल्डिग्स है, उनको आपने नहीं पकड़ा है ।

उप-सभाध्यक्ष (श्री जगदीश प्रसाद माथुर) : आप उनको लिस्ट दे दीजिये और वे उनको अरेस्ट करेंगे ।

DR. K. MATHEW KURIAN: Are you prepared to take action . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR): Please do not interrupt.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: But we must have some specific information. You see a big house and immediately say: He is a smuggler; arrest him. That kind of mere statement is not enough. He must give some tangible evidence. If I go on arresting all the owners of multi-purpose houses, that will lead us nowhere. Wherever there is a doubt about the source of the income or when some new construction takes place in a big way or when some fixed assets are being created by some people, our people go and try to ascertain facts not only from the income-tax people and customs people, but from others also. If the hon. Member is interested in the figures relating to Delhi, I can tell him in how many cases we have initiated action. The number will be impressive. There is no use saying that all the owners of big houses are benami proprietors. If the hon. lady Member has any specific information, she can give it to me and I will see that the big fish is put behind the bars. This assurance I am reiterating.

Therefore, Sir, still the question may come up as to why the smuggled goods are still coming into the market. I have never said that we have been able to stop smuggling totally and I was explaining as to why the smuggled goods are still coming into the market and I explained the situation which exists at the originating points of Dubai, Hong Kong and other places. As a result of this, Sir, huge stocks have piled up there and these are being sold as distress sale and at rock-bottom prices. If they bring about ten consignments and even if six or seven are caught, two or three or four of them can be sold and they can make good the loss which they incur in this process. Therefore, it is not correct to say that the smuggled goods are not coming in. Smuggled goods are coming in still and we have not yet been able to break this racket completely. But, Sir, what I want to emphasise is that this charge is not correct and it is not correct to say that the Government has slackened its efforts. Instead of making such blanket charges that the elections are coming and the people are taking money from these smugglers, etc., I would like the honourable Members to give me some positive information and I would like to have some positive information from the honourable Members and if they have any, they can give it to me and the Government will take action.

SHRI SANAT KUMAR RAHA: What about the boats "Durga" and "Kali"?

SHRI PRANAB MUKHERJEE: The whole difficulty about this is, Sir, that many times information about this has been given and we have given information about "Durga", "Kali" and about "Sokti". I can tell the honourable Member that out of the 20 boats which we have received, 13 are still working and only one has been damaged. But, Sir, from October onwards we have been hearing that this has been sabotaged None of them has been sabotaged; neither "Kali" has been sabotaged nor "Sokti". These are sophisticated boats and when they are put into operation, they may develop some technical snags. These snags are removed and they are repaired and after repairs are carried out, they are put into operation. I do not know of any mechanised boats in the world which can work continuously and without any trouble. These boats are to work and are put to work for about 36 hours or 48 hours continuously without any rest and,

therefore, sometimes some snags may develop. But it is not a fact that these boats have been paralysed or sabotaged or destroyed. I can tell the Members that out of the 14 boats, Sir, only one boat has been damaged irreparably and it is because of an accident about which Mr. Kulkarni mentioned the other day. It crashed against a rock and as per the report of the technician, it is not possible to repair it. Except that, out of the 20 boats which we have received, 14 have been put into commission and 6 are yet to be equipped with machine guns and other equipment. Thirteen are operating and they are working. One of them occasionally may go out of gear because of the fact that some snags may develop. But, as soon as these snags are removed, they are put into operation. "Kali" and "Durga" have given very satisfactory results and I have many times explained it on the floor of this House. So, this is not the point. Still certain smuggled goods are coming and I have explained the reasons for that.

Another information also I can give to the honourable Members and it is this that the quantum of illegal remittances has been reduced to a considerable extent. Last time also I mentioned this and gave certain figures and those figures are not readily available with me now. But, Sir, I can tell the honourable Members that the legal remittances from abroad which were a source of foreign exchange for the smugglers at the originating points have increased, that is, from Hong Kong, Dhubai and from the South-East and East African countries and these were the moneys which were utilised by the smugglers as foreign exchange to purchase the smuggled goods. If the smuggling went on unabated, there was no reason why the legal remittances should increase as it is not a fact that suddenly a large number of people have gone across the seas and settled abroad. The increase in the remittances in the legal way is also an indication that the effect of smuggling has been reduced to a certain extent. But . . .

SHRI J. S. ANAND (Punjab): What is the quantum of increase?

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I gave the figures last time. If the honourable Member is interested in it, I can give it again and I can tell him that it is an impressive one in some respect.

Regarding smuggling and other things, Sir, I am not quite sure whether I have been able to convince the honourable Members. Anyway, I have been able to give some figures and I have been able to explain the reasons also . . .

SHRI BHUPESH GUPTA: What about the transfer of the officers?

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, Mr. Bhupesh Gupta is mistaken because, for the MISA, there is a separate Cell and we are looking into the matter. And also, Sir, the transfer of one individual officer—I hope Mr. Bhupesh Gupta will excuse me for saying this—does not mean that the entire operation will go down . . .

SHRI BHUPESH GUPTA: I am also quite clear that as far as the transfer of one individual officer is concerned, it does not necessarily mean anything. But, here in this case, we knew it for the last few months and we, in fact, knew since last year that Mr. Badami had been put in charge of it from the official side.

He was doing excellent work and he became the target of attack of smugglers and others. In fact, some people even approached us to stop this kind of transfers. Now that transfer has taken place, well, Sir, in retrospect at least; we think that some of the information that has been given to us is correct. Therefore, I think, Sir, in the middle of the drive or when you are continuing the drive, a person who has been dealing with it should not be transferred Changing horses in midstream is very, very bad in such matters. Now, this requires to be explained, all the more so when in some sections of the Press during the last few days we have come to know that Mr. Taneja—I do not know what he is—has not been given extension due to some extraneous pressure, despite the fact that your Ministry, Department of Banking of your Ministry, and Reserve Bank hace recommended, I am told, that Mr. Taneja, Chairman of the Board of

Directors of the Central Bank, should be given extension. I have got some information, but I am not divulging it. Similar is the case with the Chairman of the Board of Directors of the Bank of Baroda also.

These things are causing a little suspicion not only amongst us but among many members on your side also. They may not be speaking all that here. But everyone knows, Mr. Pranab Mukherjee, that many MPs are worried nowadays because of the manner in which certain people, influential people, may be politically connected, are getting officers transferred. This is causing a little worry and enxiety amongst many of us. I have already written to your chief, Mr. Subramaniam, that when the Finance Ministry's Consultative Committee meets the day after tomorrow the question of these appointments and transfers should be discussed.

SHRI A. G. KULKARNI (Maharashtra): This problem really came in the case of the Birla inquiry being held.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Mr. Kulkarni is correct. Mr. Badami is not looking into smuggling cases. Let me explain this. He is looking after the special cell. He is Director, Investigation. I think I will explain the position in detail so that there is no misunderstanding in the minds of hon. Members. I do not know how the hon. Members got this impression. I can tell the fact.

So far as the Birla groups are concerned, which are being looked after by the special cell, only a couple of weeks ago I gave a reply, a detailed, exhaustive reply, to a question of Mr. Kalyan Roy where I spelt out all the details, what are the cases, how much amount is outstanding, at what stage these cases are. Therefore, it is not a fact that all these cases have been dropped as a result of transfer of certain individuals. If Mr. 'X' was to look after these cases, in place of Mr. 'X' if Mr. 'Y' comes, he will look after the special cell, which is looking after cases of big houses. I can give some figures. In the case of Birla group, regular assessments are 990, reopened cases 42, Bijoria and Jalan group: 310, re-opened assessments 37; other groups, regular 180. In between, on the 31st March, certain more cases might have been reopened or certain more cases might have been disposed of.

Therefore, it is not a fact that cases which were against the Birlas have been dropped and the functioning of the special cell has been stopped. Special cell will go on functioning. The whole question is whether some officers have . . .

SHRI BHUPESH GUPTA: Why should he say so much? You know it very well and records will show that we brought so many facts about the plan to get Mr. Guha removed or transferred to his original point. You are investigating into the Birla cases. His house in Calcutta, in Bhawanipur, has been burgled. Influential telephones have come from Calcutta. Many things have happened. We are in possession of these. You are in the majority. You can deny it. But truth remains truth even if it is denied with the strength of the majority.

These are facts. I suggest that let there be an investigation by a committee of this House into the specific allegations that we have made regarding the transfer of Mr. Guha. Was it at the instance of Mr. Birla and certain influential people who have contacts in Delhi? I hope the officer concerned will not be prosecuted for this reason.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I have already explained the position regarding Mr. Badami about whom Mr. Bhupesh Gupta and Mr. Kulkarni mentioned. I can assure them that the cases have not been dropped.

SHRI A. G. KULKARNI: I fully agree that any officer wheher he is Badami or somebody else will carry out the work. This inquiry is going on for the last 4 years. Certain cases have been opened and reopened. Some cases have gone to the High Court. You say that some cases are in the High Court. They will be in the High Court for the next 25 years because Birlas are moneyed people and they can engage any number of lawyers. The point is: what is the quick remedy which is re-

quired for the satisfaction of the people in order to create credibility of the political parties and democracy in this country?

SHRI PRANAB MUKHERJEE: So far as credibility is concerned, I do not know whether I will be able to satisfy Mr. Kulkarni and the other hon. Members. I can speak of the facts. As I have explained, the job of the Special Cell for which it was created will continue unabated, uninterfered and uninterrupted. I have due respect for my officer and I have confidence in him. But at the same time, I do not accept the proposition that with the removal of one individual, the entire functioning of the Government will come to a standstill.

Mr. Bhupesh Gupta raised some points regarding the transfers and appointments in the banks. I would like to suggest that it was done in consultation with the Reserve Bank of India which is the competent authority to give advice to the Ministry of Finance in regard to the appointment of Chairman, Managing Directors. There are certain rules. These are not extraordinary appointments. The term expired and the new people had to replace them. The Government has to act according to the rules. I do not think there is anything wrong in it.

SHRI BHUPESH GUPTA: I am not speaking for any individual. I want to ask whether in the case of Mr. Taneja there was a recommendation by the Department of Banking, Reserve Bank of India and your Ministry that an extension should be given. I am not the man to judge it. What worries me is that the extension has not been given because some influential people or some groups were against him because they did not get certain accommodation from him. Now, it is for you to tell that the Reserve Bank of India did not recommend and you did not favour anybody and that it was done as a matter of routine.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: The Government has certain set rules regarding extension. If somebody is to be given extension, it has to be done under the rules of the Government. As I have explained, the appointment of all the top executives in the nationalised banks is being made in consultation with the Reserve Bank of India. Therefore, it is not a fact that the Reserve Bank said something and something contrary to that was done.

SHRI BHUPESH GUPTA: Did the Banking Department say anything?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR): This is the only answer which he can give.

SHRI BHUPESH GUPTA: He can give many answer if you allow him.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR): I have allowed.

SHRI BHUPESH GUPTA: My question is . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR): Your question was very clear.

SHRI BHUPESH GUPTA: What did the Reserve Bank say? Was the Banking Department of the Ministry consulted? What was their opinion?

SHRI PRANAB MUKHERJEE: It is the Banking Department which is to suggest because it is for the Banking Department to initiate the file. Therefore, if he wants to know at what stage what answer came and what noting came, it is not possible for me to answer that. But the Banking Department is the administrative department so far as the top appointments of the banks are concerned. These are the highest appointments which are made by the Appointments Committee of the Cabinet but the initiation must start from the Department itself. That is the normal procedure. I don't think, Sir, there are any other points which the hon. Members mentioned.

DR. K MATHEW KURIAN: What about the Ghai's case?

SHRI PRANAB MUKHERJEE: About the Ghai's case and certain other points which the hon. Member has mentioned, he

is already aware of the position which has been communicated to him by the Finance Minister through a letter. But, I understand, Sir, he has raised some fresh points and those will have to be looked into and it is not possible for me just now to give a satisfactory reply.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR): The question is:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1975-76, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR): We shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

Clauses 2 and 3 and the Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I move:

"That the Bill be returned."

The question was proposed.

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): Sir, my friend, Mr. Pranab Mukherjee, acted here more as an advocate than as a Minister replying to the questions that we raised. Well, everybody knows that the Government makes the appointments, and in this case, the appointment has been made by the Government. This is not disputed. What is disputed is this that this appointment has been made or the extension has not been given in the case of the Chairman of the Board of Directors of the Central Bank in disregard of certain initial recommendations in favour of an extension. And I mentioned the Reserve Bank in this connection. He has not up to now denied that the Reserve Bank did not make any such recommendation. Well, we have also heard many other things and I need not to go into them. But somehow or the other, the whole thing has left a very bad taste in the mouth and it is being talked in the lobbies, in the press, and the Government should clarify the position by giving a more convincing answer. I am told that Mr. Taneja is not liked now because he is supposed to have good relations with the staff, that is to say, the employees. As you know very well, Sir, the employees are a very well-organized trade union here. And when I am making the statement, I do say with some sense of responsibility on the basis of the information that I have and which I cannot just dismiss. I have other information but today, I shall not bring that because it is of a very serious nature. In the case of both the banks, and particularly, the Central Bank of India, the manner in which the appointment of the highest post has been handled is open to suspicion, to put it mildly.

With regard to Badami also, the same thing is being said. Not only that, We were apprehending that he would be going just as Mr. P. K. Guha was removed in the middle of the investigation. We know for a fact from people very close to the Birlas that the Birlas were boasting that this man would go out of the investigation, and he did go out of the investigation.

We tried to stop it by writing to important Ministers, including, I believe, to the Prime Minister. But, nothing happened. It seems that our voice is not heard. Whether we belong to this side or to that side, it is only the voice of Birlas which is heard in the Council of Ministers in this country and that causes us anxiety. We are all in favour of giving encouragement to honest officers. In fact, Sir, I would like the honest officers, officers with integrity, recognised and rewarded. The other day I read a circular issued by the Prime Minister's Secretariat to the officers to the effect that no one be afraid of taking initiative, even committing mistakes, and in that circular it had been pointed out by the Prime Minister that sometimes the officers are persecuted because they do not give licences according to the demands of the business people and so on. Now, some assurance has been given in the circular which has been issued to the Government depart-

ments, some assurance has been given to honest officers of integrity but what is happening; actually the opposite is happening, exactly the opposite is happening. Honest officers are being hounded up, persecuted, victimized, charge sheeted, harassed, transferred; this is going on the one hand and the Prime Minister's Secretariat issues sermons and circulars on the other, stating that the officers should be treated well, given encouragement even if they commit mistakes and that they should not at all be scared of those people who seek licences, permits, etc. Therefore, let us know where we stand today. This is what I want. Now, you may disregard the opposition. This Government is developing a habit now of totally disregarding what we say on this side of the House. Now, these are not political matters. These are issues on which we can come to a common understanding from both sides of the House. In fact, what I say here and what they say there, very often there is no disagreement basically. There are private Members, what do they say? Why should not the Government listen to some people sitting somewhere, some friends somewhere? Why has Mr. Romesh Thapar resigned? He was a Director, a member of the Board of Directors of the Central Bank. Has he not issued a statement complaining of the manner in which the top post has been handled? And, Romesh Thapar is a man who is not a *persona non grata* with the Government. In fact, the Government appointed him as a memer of the Board of Directors of the Central Bank of India and he finds it difficult to continue on that body because of the manner in which the top posts are being handled. Well, these matters certainly are open to suspicion and question. Now, I want to finish by saying, therefore, that Mr. Pranab Mukherjee should not encourage that habit because we know the Ministers also go. What is the guarantee Mr. Pranab Mukherjee—Badami has gone today—that tomorrow you will not go.

DR. K. MATHEW KURIAN: Go to West Bengal.

SHRI BHUPESH GUPTA: Ganesh went. Everybody knows why he went. What is your guarantee or stability? You are the most unstable person because you are a Minister. Officers have got red-tape rules which take time. You require only a Cabinet reshuffle. Therefore, I say don't encourage this habit of transfer of this type because at times with the small man also goes the big man and I am sure you are an honest man and I am sure you are trying to do good things. But, what is the guarantee that Birlas will not be after your head if you do not salute to the Birlas. Birlas are there, sharks, and they are prowling around the seats of power. They have got people, they have got men around the seats of power and they will exercise pressure and influence in this manner. Listen to us. We have no axe to grind in this matter. We have nothing to do with the Birlas and others. Therefore, we should be listened to. Why were not the Bank employees consulted? Bank employees' association is a responsible association. I hear from representatives of the employees of nationalised banks who are on the board of directors that attempts are being made due to certain extraneous pressures and influences in order to accommodate certain people for certain other purposes which have nothing to do with the proper and efficient functioning of the banks or financial institutions of our country. (*Time-bell rings*). So, be a little careful.

We are a little disturbed about the developments in Uttar Pradesh.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR): Please conclude. You have to speak on Jaipur also.

SHRI BHUPESH GUPTA: Yes, we cannot leave Jaipur. But we are a little disturbed about Uttar Pradesh because we find that when the Uttar Pradesh Government should be taking steps for the improvement of the conditions of the people through implementation of the land ceiling laws, running the public distribution system and supplying essential goods to the people and stopping oppression of and attacks against the Harijans, the ruling party people are involved in factional fights of the worst type. I say, it is no good. There are my friends there to do something good for the people of West

Bengal and I do not care who is what. They should all work together for the well-being of the people of Uttar Pradesh.

In this connection, Mr. Vice-Chairman, I am very much pained to say one thing. I do not think the Governor of Uttar Pradesh, Dr. Chenna Reddy is behaving according to the Constitution and according to the standards laid down through years of working of the Constitution particularly with regard to the office of Governor. Why should the Governor ask the Inspector-General of Police and others to submit reports to him directly, bypassing the Ministry? I cannot understand it. Why should the Governor ask the Information Department or the Publicity Department that whenever he goes to a holy place, his visit should be filmed and shown to the people? Why should the Governor, Mr. Chenna Reddy propose that a temple of Ganeshji be constructed in the Raj Bhavan? Why are all these things being done? Has he been advised by some people? Has he consulted the Ministry? I should like to know. Many of us have been here for many years but we have never heard such things before. Have you ever heard of a Governor asking the Publicity Department that whenever he went to a holy place the visit should be filmed? Did you ever hear of a Governor asking for building a Kali temple, a mosque, a church or a gurudwara or something else in Government houses? We are supposed to be a secular State. Why is it being done and why is the Governor behaving in this manner? Sir, Mr. Chenna Reddy, after all, should be a little careful. He was subjected to structure of a court as a result of which he had to resign his ministership. He was once found indulging in malpractices in election as a result of which he had to go. Today it seems Mr. Chenna Reddy is getting involved more and more in party politics. This should not be done: this should be stopped. Let the Congress Party stop it in the way they think the best but why should the constitutional office of Governor be misused in this manner? I understand that some people at the Centre, some Ministers at the Centre are directly encouraging Mr. Chenna Reddy in this manner.

SHRI RABI RAY (Orissa): Who are they?

SHRI BHUPESH GUPTA: Find it out. Why should I find it out for you?

(Interruptions)

So, Sir, I do not wish to say more. You have been very kind to me. Jaipur is coming, a more interesting subject, and I hope Mr. Pranab Mukherjee will say something more on this subject. As far as the Appropriation Bill is concerned, I have nothing much to say. I have only one thing more.

The other day I raised the question of two Naxalite prisoners under sentence of death.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR): You have raised so many points that he will forget!

5 p.m.

SHRI BHUPESH GUPTA: This is very important. The two Naxalite prisoners are Kistayya Gowd and Boomaiah. Their sentence has been stayed by the Andhra Pradesh Government. We intervened in it. The Chief Minister, Mr. Vengal Rao, personally told me that he would like the sentence to be commuted. Now, Sir, I understand, I have got the document from Andhra that the Andhra Pradesh Government has requested the Centre to commute the death sentence but the Central Government has refused. This is too serious. It should be open to the State Government to commute the death sentence. You have commuted the sentence on Miss Shamim Rehmani. Now the girl is out. It is good that you have done. So, why should these two people be awaiting execution when the Andhra Pradesh Government wants commutation of the death sentence? The Chief Minister is personally in favour of the commutation of the death sentence. He has himself told me this and I am telling on the floor of the House for the public to know. He has sent the request to the Centre. Now, Sir, Mr. Pranab Mukherjee should convey it. I once again appeal to the Government of India, through you to the President of India who acts on the advice of the Prime Minister that the commutation should be granted. Many people have approached the Government there. We have approached the

Government here. These two Naxalites shall not die. They shall not be hanged. We are told preparations are being made in order to get them hanged It is a matter of great shock and shame, especially when the Andhra Pradesh Government itself is ready not to hang them. The Central Government should endorse the request of all of us and the Andhra Pradesh Government and commute the death sentence on these two Naxalite prisoners. They are still in the Hyderabad jail or in some other jail of Andhra Pradesh.

DR. K. MATHEW KURIAN: Sir, in the course of my speech I had raised two specific questions. One was the specific case of smuggling of leopard skin and I had mentioned certain officers of the Directorate of Revenue Intelligence who have been in collusion with these people, who have been indulging in the smuggling of leopard skin. I also mentioned about the involvement of a foreign airlines working in India. The hon. Minister very conveniently glanced over the whole issue. He wanted specific instances and I have given a specific instance of smuggling of leopard skin. I hope the hon. Minister will at least admit that this is a specific charge that I am making. I have given names of the people. I hope he will at least promise for a thorough investigation into this case. This is not a blanket charge that I am making. This is my first request.

Secondly, I made a reference to two international multi-national companies, one is the IBM and the other is the Coca Cola. Since 1971 Coca Cola Export Corporation has been repatriating abroad foreign exchange in the form of service charges to the tune of 156 per cent of the export value. Sir, we have seen export profits being transferred but now you find service charges also being repatriated which according to my understanding is illegal. I do not know how the Government has allowed this. I would request this question be looked into. Then I referred to blatant anti-labour trade practices in the IBM. I would request the hon. Minister to see that the multi-national corporation like IBM working in India do not enter into unfair practices as I have referred to yesterday.

Lastly, Sir, I would request the hon. Minister to give a categorical assurance, particularly in the background of the enforcing of Government's decision regarding curbing smuggling activities, unearthing black money and so on, with regard to the promotion of Income-tax Officers, especially class II officers who have been promoted to Class I. They form the core of the basic framework of our implementing machinery. A large number of these people who have 10 to 20 years of experience, should be given incentive in terms of promotional chances etc. Unless the Government follows a policy of promoting these officers, I am afraid all the raids conducted by the Government will be infructuous because immediately after the raids are made, assessments have to be made, follow up action has to be taken by these officers who are in the Income-tax Department and who are in other Central Revenue and Excise Departments. They are the people who have to take initiative and if they are demoralised, I am afraid we will not be able to achieve the desired results. I will therefore request the hon. Minister to give us a categorical assurace that the Government will follow a positive policy of promoting these officers and give them incentives so that they do good job and those officers who are experienced and able will be rewarded rather than penalised for their experience.

Lastly, Sir, I would like to say that today, on 6th May, the Kerala Assembly is meeting. It is meeting today in the backdrop of bargaining, purchasing a large number of votes and encouraging dissentions from the Opposition to the ruling Party.

Sir, as you are aware, Kerala Government is a government led by the C.P.I. with major chunk of the support coming from the ruling Congress. The existing Government has lost its majority, but they continue to remain in power by purchasing votes from the Opposition, and so on, which I consider unhealthy, unholy and unfair, and so I would demand that the Kerala Government should resign altogether and fresh mandate of the people should be sought. I hope the Government of India will understand the implications of

remaining in power while the political base of their so-called United Front has broken. I hope the Government will do the fair thing to meet the electorate and get a verdict. I am sure the people of Kerala will throw these people out of power.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY (Uttar Pradesh): Sir, before the third reading of the Appropriation Bill is over, our House, the Council of States, has an opportunity to consider some of the situations in various States. Sir, this is specially important because the Appropriation Bill deals partly with the plans and investments that are being made in some of the States. I want to refer to the State I represent, viz. Uttar Pradesh. Uttar Pradesh today is in a state of complete financial bankruptcy. I am not sure whether the Uttar Pradesh Government will be able to pay the salaries of its own employees after July. This is the situation Uttar Pradesh has reached.

Then, Sir, the law and order situation in Uttar Pradesh has completely broken down. There it is impossible now to travel alone during the night time. There is road piracy going on on a scale unprecedented before. Trucks cannot travel in Uttar Pradesh alone at night. They have to go in a convoy of five or six together.

On top of it, there is a complete breakdown in the administration in Lucknow itself. I went there recently and I visited the offices of Secretaries of various Ministries, and to my surprise I found them reading novels like '*Last Time I Saw Paris*' and recalling their wonderful experiences. I asked them why they were not working and reading novels. They said that there was no work for them; all the work was being done by two Personal Secretaries of the Chief Minister from the Chief Minister's residence. This is what everyone of the Secretaries said. I would urge upon the Members of this House to consider how this biggest State of India is in complete mess. All the projects that were sanctioned during the Uttar Pradesh elections have not proceeded even a step further. The dam in Tehri Garhwal which was promised during the election time as a great new venture has not even taken off the ground. I would not mention other projects where after the foundation stone even the foundation stone is being covered by dust. On top of it, this Chief Minister, Mr. Bahuguna...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR): Don't make it. U.P. Assembly.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: This is Council of States. This is very important. I am not going any farther than Mr. Bhupesh Gupta went. This Chief Minister took a vow: भगवान की कसम खाता हू कि...

This is what the election posters brought out during the elections that he will fulfil all his promises. He has not fulfilled any one of his promises and the only activity he seems to have been engaging in is to fly on State expense in the State aircraft, come to Delhi, see off his wife on a visit to the Soviet Union and return. This seems to be the sum total of the activity of this Chief Minister. Therefore, this Government ought to know that members of Parliament are exercised by the way this big State, this massive State, this largest State is being run and if we could communicate to the State Government our displeasure, it would be doing a great service to the people of Uttar Pradesh.

श्री रबी राय : उप-सभापति जी, यह बिल का तीसरा वाचन है। मैं दो मुख्य सवालों के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मामल में प्रणव बाबू को भी याद दिलाना चाहता हूं कि चुनाव के समय तरह तरह के आश्वासन और वचन सरकार की ओर से दिये जाते है और आप स्वयं जानते है उप-सभापति जी, कि उत्तर प्रदेश में विधान सभा के चुनाव के पहले करीब 600 प्रोजेक्ट्स का प्रधानमंत्री ने शिला न्यास किया था और उसके बारे में हिन्दुस्तान टाइम्स मे विवरण निकला था। 15-20 दिन पहले भी वे क्यों क्रियान्वित नहीं हुए वह भी निकला। मैं इस पृष्ठभूमि में प्रणव बाबू को याद दिलाना चाहता हूं क्योंकि मैं जिस स्टेट से आया हूं और प्रणव बाबू उड़ीसा के सवाल के बारे मे जानते है इसलिये कि यह राज्यों का जो मामल है उसक केंद्रीय सरकार से सम्बन्ध

रहता है इसलिये मैं आपकी खिदमत में यह रखना चाहता हूं ।

एक तो मैं चाहूंगा कि प्रणव बाबू इस बारे में जवाब दें कि चुनावों के पहले इस तरह के दो प्रोजेक्ट्स का, नन्दिनी सत्पथी के चुनाव के पहले, शाहनवाज़ खां ने शिलान्यास किया । एक तो मालनटोली प्रोजैक्ट और दूसरा लीड का प्रोजेक्ट है । ये दो तीन साल पहले शाहनवाज़ खां यहां से गये और कटक के वोटरों को फुसलाने के लिये मालनटोली और लीड कारखाने का उन्होंने शिलान्यास किया । मैं चाहता हूं आप बतायें कि भारत सरकार के भूतपूर्व स्टील मिनिस्टर के० डी० मालवीय ने उड़ीसा सरकार को बता दिया कि इसको पांचवी पंचवर्षीय योजना मे हाथ में नहीं लेगे । इसी प्रकार पारादीप फर्टिलाइज़र को सरकार ने क्लियरेंस दिया है, लेकिन इसके बारे मे कोई जिक्र इसलिये नहीं हो रहा है कि फ्रांस की कम्पनी विदेशी मुद्रा देने को तैयार है लेकिन भारत सरकार का जो उस बारे में योगदान होना चाहिये वह नहीं हो रहा है । वहां प्रधान मंत्री चली गई, 18 लाख रुपया खर्च हो गया, वह काम नहीं हो रहा है ।

उसी तरह से रेल मे इतनी पार्शियलिटी है कि उड़ीसा कीपटरी का आंकड़ा लें तो वह सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है । पारादीप के साथ बांसपाणी मे 36 लाख की योजना है । केन्द्रीय सरकार कह रही है कि आप 50 परसेंट दो । इस साल केवल 1 लाख रुपये का इन्तजाम हुआ । इसलिये केन्द्र सरकार की ओर से जो योजना का वचन दिया गया है उस पर भी राज्य सरकार खर्च नही करती है । इसका मतलब यह है कि राज्यों में लोगों का असन्तोष और फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है । उस पृष्ठभमि में मै आपकी खिदमत में कहूंगा कि अभी उड़ीसा में दुर्भिक्ष की स्थिति है ।

इन चार-पांच जिलो में दुर्भिक्ष का एलान होना चाहिये । पहले कुछ राज्यो में दुर्भिक्ष कि स्थिति से जुडने के लिये कुछ नई रेल लाइने दी गई लेकिन अब इन राज्यों में कुछ करने के लिये केन्द्रीय सरकार सोचती नहीं है । मेरा कहना यह है कि इस तीसरे भाषण में मैं यह चीज लाना चाहता हूं कि अभी आप देखेंगे कि पारादीप सबसे गम्भीर बन्दरगाह है । अर्थ मंत्री बनने से पहले वे उस मंत्रालय के मंत्री रह चुके हैं । वहां की जो स्थिति है वे अच्छी तरह जानते हैं ।

Deliberately the Government of India is starving the deepest port in the country, i.e., Paradip. वहां फर्टीलाईज़र नहीं हो रहा है । वहां कारखाने नही बना रहे हैं । स्टील को तो छोड़िये । इस मे सबसे पहले नम्बर पर है उड़ीसा और इसको शुरू से ही नज़रअन्दाज किया गया है । मैं इस सिलसिले मे कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार पिछडे राज्यों के प्रति केन्द्रीय सरकार के उदासीन भाव हैं उसके बहुत भयंकर परिणाम निकलने वाले हैं । इसलिये मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि सरकार गम्भीरता से सोचे और जो पिछड़े हुए इलाके हैं, राज्य हैं उसका ज्यादा सैन्ट्रली इन्वैस्टमैंट हो । उसकी जो मांग है, जायज मांग है उस पर सरकार को सोचना चाहिये ।

मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि अभी फिलहाल अखबार में निकला है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा 7 हजार मिलियन टन कोयला उडीसा में निकला है । वह सम्बलपुर और सुन्दरगढ़ दोनों के बीच जो इलाका है उसे रामपुर कहते हैं वहां से निकला है । बोक्साइट में भी उड़ीसा नम्बर दो पर है एंड मैकिण्ड इन दी वर्ल्ड और यह आस्ट्रेलिया के बाद है जहा से अल्मोनियम निकलता है । मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को इस तरफ विशेष ध्यान देना चाहिये ।

दूसरा सवाल यह है कि नेशनल युनियन जर्नलिस्टों को भी मैं बधाई देना चाहता हूं । अपने केस को लेकर उनके दिल्ली हाई कोर्ट में जाने के बाद भारत सरकार खुद मान चुकी है कि हम दुबारा वेरीफिकेशन करेंगे । नेशनल युनियन

ल्जर्नलिस्टो को आप जानते हैं कि रेप्रेजेंटेशन नहीं मिला था और वैरीफिकेशन के बारे में सरकार के सामने जो आंकड़े थे उसको गलत बताया था इसलिये यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट में गया और सरकार को झक मार कर कहना पड़ा कि हम दुबारा वैरिफिकेशन करेंगे । मैं चाहूंगा सरकार जिस चीज का वचन देकर दिल्ली हाई कोर्ट के सामने आई उसके लिये जर्नलिस्टो को बधाई दी जाये । जिस तरीके से उनके सारे अधिकारों के बारे में भारत सरकार ने जो अतिक्रमण किया था उसको वे हाई कोर्ट के सामने ले गये और इसी डर के मारे केन्द्रीय सरकार को यह मानना पड़ा । जिसके चलते नेशनल यूनियन जर्नलिस्टो को सारा मुकद्दमा वापस लेना पड़ा । इसमें नेशनल यूनियन जर्नलिस्टो की जीत है । मैं उम्मीद करता हूं कि वैरीफिकेशन के बाद प्रजातन्त्र तरीके से नेशनल यूनियन जर्नलिस्टो को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा । इतना ही कह कर मैं समाप्त करता हूं ।

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, the Appropriation Bill is almost like an omnibus and as a result various subjects have come within its purview. Some of the points relate to other Ministries and I would draw the attention of the respective Ministries to them. To two points I would reply. One is the specific case mentioned by Dr. Kurian about the smuggling out of leopard skin. Yesterday he mentioned it in the discussion and I have noted it. I would like to investigate and find out whether any official collusion is there. I can assure him that if anybody is found guilty, proper action will be taken against him Regarding financial allocation and other things relating to UP or Orissa, you will agree with me that it is not possible for me just at the moment to reply. I will pass on the sentiments of the hon. Members and their views to the concerned Ministries.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR): The question is:

"That the Bill be returned".

The motion was adopted.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION ON POINTS ARISING OUT OF ANSWER TO STARRED QUESTION 39 DATED 29TH APRIL, 1975 REGARDING SEARCHES AT THE PALACES OF FORMER PRINCELY HOUSES OF JAIPUR

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, we are back to the subject of the palaces and residences belonging to the former ruling family of Jaipur which have been searched, with the result that a lot of gold, diamonds, jewellery, foreign currency and many other things have been found. Now, I would like the hon. Minister to give us the results of the searches. I want the latest results because I understand that one necklace has been found which was concealed behind a framed photograph which costs about Rs. 1 crore. It is supposed to be a world famous necklace, the possession of which was denied by the ex-Maharani. Now, it has been found. Well, I should like to know the circumstances in which it has been found and more information about it. We also have come to know that a diamond piece has been found from the room of the ex-Maharani, Shrimati Gayatri Devi, which costs, again, Rs. 1 crore, apart from any other things that have been found there.

Sir, as you know, this is the paper with which I am associated, namely, the New Age. On the 31st October, 1971 it published a report in which attention was drawn to the hidden wealth in the Jaipur palaces. And in fact, at that time the New Age wrote in that issue—

"The late Maharaja of Jaipur, Sawai Man Singh, was indeed a clever man. He had even anticipated such demands as takeover of the ill-gotten wealth of princes. So he took care of all contingencies. A trust was set up abroad to provide succour for the rainy days to the members of his family . . ."

"Nobody knows the value of the jewellery with the Jaipur House. But we know that 39 buildings are owned by it outside Jaipur. And there is a bungalow in London, and a farm at Santhill in Britain, besides unknown balances in Swiss banks."